● वर्ष-3
● अंक-57
रायपुर, शनिवार
14 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› छत्तीसगढ़ के इन दो संभागों ...

डार्विन-आइंस्टीन की थ्योरी को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अपनी थ्योरी खुद बना लें

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जो द्रव्यमान और ऊर्जा (ई = एमसीद्द) की समानता को व्यक्त करता है। याचिकाकर्ता राज कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में डार्विन के सिद्धांत और आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें गलत पाया और इसलिए, उन्हें शैक्षिक रूप से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के तर्क का जवाब देते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि फिर आप खुद को फिर से शिक्षित करें या अपना खुद का सिद्धांत बनाएं। हम किसी को भी अनसीखा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जिसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका नहीं हो सकती है। पीठ ने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका नहीं हो सकती है, जिसे मौलिक अधिकारों के मुद्दों से निपटना है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि आप मानते हैं कि वे सिद्धांत गलत थे, तो सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना-देना नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? अंग्रेजी प्रकृतिवादी डार्विन द्वारा प्रस्तावित विकास का सिद्धांत बताता है कि सभी जीवित प्राणी प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुए हैं। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण श्व = द्वष्ठ कहता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान (पदार्थ) विनिमेय हैं।

26 वीक प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन केस, एम्स से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक विवाहित महिला के भ्रूण के स्वास्थ्य और चिकित्सा स्थितियों को इंगित करने के लिए एक ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगी, जो 27 वर्षीय मां के एक दिन बाद अपनी 26 सप्ताह की गर्भावस्था को तत्काल समाप्त करने की अपनी याचिका पर अड़ी हुई थी। दो को कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह दी थी। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी, जिसके एक हफ्ते बाद कोर्ट ने पहले गर्भपात की अनुमति दी थी लेकिन बाद में दो जजों की बेंच की राय अलग-अलग होने के कारण इसे रोक दिया गया था।शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले एक नई चिकित्सा राय की आवश्यकता थी क्योंकि महिला की पिछली मेडिकल रिपोर्ट में उन दवाओं के प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी जो उसने ली थी। वह अपने प्रसवोत्तर अवसाद के लिए दवा ले रही थी और न ही उसके चिकित्सीय नुस्खे त्रुटिहीन थे। सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने कहा कि निस्संदेह एक महिला का प्रजनन अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत होना चाहिए। लेकिन समान रूप से हम जो कुछ भी करते हैं वह अजन्मे बच्चे के अधिकारों को संतुलित करना है क्योंकि कोई भी बच्चे के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। इसमें कहा गया है कि जबरन गर्भधारण या नाबालिग जिसे जन्म देने के परिणामों का एहसास नहीं है, के मामले में भ्रूण को समाप्त करने का विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है।

अदालत ने संजय सिंह को चेताया

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अदालत कक्ष में राजनीतिक भाषण नहीं देने की चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसे भाषण दिए जाते हैं, तो अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी का निर्देश देगी। न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने अदालत के समक्ष दावा किया कि ईडी ने अडानी के खिलाफ एजेंसी को दी गई उनकी शिकायत पर काम नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा, कोई असंबद्ध मामला नहीं है। यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं। मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहूंगा। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जब जांच एजेंसी ने उन्हें पहले दी गई हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया। इस बीच, संजय सिंह के वकील ने अदालत से उन्हें महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और अन्य द्वारा लिखी गई।

अब अयोध्या में अरब देशों की तर्ज पर होंगी मस्जिद

नई दिल्ली। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन मिली थी। इस जमीन पर मस्जिद बनाई जानी थी, मगर अब इस मस्जिद का डिजाइन बदल दिया गया है। पहले मस्जिद का डिजाइन आम तौर पर दिखने वाली मस्जिद की तरह था मगर अब इसका डिजाइन एकदम अलग हो गया है।

यानी अयोध्या में अब मस्जिद आम मस्जिदों की तरह नहीं बल्कि नए रूप में दिखाई देंगी। अब यह मध्य-पूर्व और अरब देशों में बनने वाली भव्य मस्जिदों की तर्ज पर निर्मित होगी। अरब देशों में बनने वाली मस्जिदों के डिजाइन से प्रेरित होकर ही मस्जिदों का निर्माण होगा। सिर्फ यही नहीं मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाएगा। गौरतलब है कि अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन मिली है। इस जमीन पर मस्जिद के अलावा अस्पताल तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण होना है। इनके निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर फारुकी ने बृहस्पतिवार को पीटीआई- से बातचीत में कहा, मस्जिद-ए-अयोध्या का डिजाइन अब बदल दिया गया है।''

उन्होंने कहा कि पहले भारत में आमतौर पर दिखने वाली मस्जिदों की तर्ज पर ही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का डिजायन तय किया गया था, जो बेहद सरल था। मगर अब ट्रस्ट ने इसके डिजाइन में बदलाव कर दिया है। इसे मध्य-पूर्व और अरब देशों में बनने वाली भव्य मस्जिदों की तर्ज पर मस्जिद बनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर रखा जाएगा।

इस मस्जिद का डिजाइन पुणे के वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया है। इस नए डिजाइन को मुंबई में गुरुवार को आयोजित की गई एक बैठक में फाइनल टच यानी अंतिम रूप दिया गया है। बता दें पहले जो मस्जिद बन रही थी अब नई मस्जिद का साइज उससे अपेक्षाकृत बड़ा होगा।

नई मस्जिद होगी बड़ी

नई मस्जिद डिजाइन के कारण अपने आकार में भी बड़ी होगी। इस मस्जिद का डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि यहां अधिक जगह भी होगी। यहां एक साथ 5000 नमाजियों के नमाज अदा करने की जगह होगी। बता दें कि अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद के अंतिम रूप को फाइनल करने को लेकर आयोजित हुई बैठक में सुन्नी, शिया, बरेलवी और देवबंदी सहित सभी मुस्लिम मसलकों के लगभग एक हजार मौलवियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट

- **पांच राज्यों में जीत का प्लान, कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट**

नईदिल्ली। देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे. कई राज्यों में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच है, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है. सभी पार्टियों ने अलग-अलग राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है. हालांकि, अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है.

वहीं, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस शुक्रवार (13 अक्टूबर) को पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है. माना जा रहा है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है. इसकी वजह ये है कि गुरुवार (12 अक्टूबर) को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की है.

एमपी-राजस्थान के उम्मीदवारों की लिस्ट भी हो सकती है जारी

कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है. इसमें कुछ प्रमुख चेहरों को टिकट दिया जा सकता है. गुरुवार को हुई सीईसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए. तेलंगाना के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे आखिर में आने की संभावना नजर आ रही है.

किस राज्य में किसकी सरकार?

देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से दो जगह कांग्रेस की सरकार है, जबकि एक जगह बीजेपी, एक जगह भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और एक जगह मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार चला रही है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं, जहां कांग्रेस सत्ता में हैं. मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि तेलंगाना में बीआरएस सत्ता में काबिज है. मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, जो एनडीए का हिस्सा है.

किस राज्य में कब होंगे चुनाव?

छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरण में चुनाव करवाए जाएंगे. मिजोरम में एक ही चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में चुनाव की तारीख बदलकर 25 नवंबर की गई है. तेलंगाना में एक ही चरण में 30 नवंबर को वोटिंग होगी. सभी राज्यों का चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को जारी हो जाएगा.

चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस, लगभग सभी राज्यों में बड़े नेताओं की सभाओं की तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करने जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीदवारों के प्रचार के लिए राहुल 16 अक्टूबर से तीन दिनों के लिए मिजोरम का दौरा कर सकते हैं। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष लालमलसावमा नघाका ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी आइजोल शहर में मार्च करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे।मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में सात नवंबर को मतदान होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में दो चरणों में सात एवं 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पांचों राज्यों में तीन दिसंबर को मतगणना होगी।

प्रमुख समाचार

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार गंभीर

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक सर्दियों के मौसम के करीब आते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने औद्योगिक प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के प्रभाव को कम करने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की जिसमें वाहन प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल, सड़कों और ROWs से धूल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट , कृषि अवशेष जलाना शामिल है। बैठक के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली और वृक्षारोपण पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन, इसकी निगरानी और क्षेत्र स्तर पर इसके कार्यान्वयन में सुधार के उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता की गिरावट को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों द्वारा जीआरएपी में सूचीबद्ध कार्यों का कड़ाई से कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय मदद से ही हुआ विकास, सुशील कुमार मोदी

पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ, वह केंद्र की सहायता से संभव हुआ और इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिला। क्या बिना केंद्रीय मदद के राज्य के 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 1.02 लाख करोड़ की राशि मिलती है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा का साथ छोड़ने के 13 महीने बाद नीतीश कुमार को केंद्रीय सहायता में भेदभाव क्यों दिखने लगा। यदि हिम्मत है तो वे केंद्र से कोई मदद न लेने की घोषणा करें। वे जिससे सहायता लेते हैं, उसे ही कोसने भी लगे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये खर्च कर बरौनी खाद कारखाना का आधुनिकीकरण कर इसे फिर चालू कराया। नीतीश कुमार क्यों उनके साथ चले गए, जिनके शासन में बरौनी सहित कई कारखाने बंद हुए, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और पलायन की नौबत आयी।

भाजपा ने किरण रिजिजू को बनाया चुनाव प्रभारी

मिजोरम। मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उत्तर-पूर्वी राज्य का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल एंटनी को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले 12 अक्टूबर को मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष और एमएनएफ नेता लालरिनलियाना सेलो ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह तब हुआ है जब 2018 के विधानसभा चुनावों में चाल्फिल सीट जीतने वाले सेलो को राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा टिकट देने से इनकार कर दिया गया था।इस बीच, भाजपा ने जतिंदर पाल मल्होत्रा को अपनी चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, चुनाव एक ही चरण में होगा।

स्पीकर हमारे आदेश को खारिज नहीं कर सकते

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने में देरी के लिए शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को विफल नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी को स्पीकर को सलाह देनी होगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की समयसीमा के बारे में अदालत को अवगत कराने को कहा। नाराज दिख रहे सीजेआई ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले लेना होगा, नहीं तो पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। पीठ ने कहा कि अगर वह अध्यक्ष की समयसीमा से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्देश देगी कि निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाये। पीठ ने संकेत दिया कि वह याचिका पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया था।

भारतीय संस्कृति का प्रभाव विदेशी महिलाओं ने अपने पूर्वजों का किया तर्पण

नईदिल्ली। भारत की विदेशी संस्कृति का असर विदेशियों पर गहरा होने लगा है। वृंदावन मथुरा में आमतौर पर विदेशी लोगों कृष्ण भक्ति में रंगीन नज़र आते हैं। वहीं अब जैसलमेर आने वाली विदेशी सैलानियों पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। कई विदेशी सैलानी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर इसे अपनाने लगे हैं। इसी का ताजा उदाहरण जैसलमेर में ही देखने को मिला है जब फ्रांस की 17 महिला टूरिस्ट ने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण भी किया। महिलाओं के इस ग्रुप में जैसलमेर के अष्टांग योग केंद्र में योग करने के बाद गड़ीसर झील में श्राद्ध तर्पण किया। बता दे कि फ्रांस से महिला पर्यटकों का यह दल बीते सात या आठ दिनों से जैसलमेर में घूम रहा है। इस दौरान महिलाओं का यह दल हिंदू संस्कृति से खासा प्रभावित हुआ।महिलाओं का कहना है कि बीते 3 वर्षों से वह लगातार योग से काफी प्रभावित है और फ्रांस में भी योग करती है। महिलाओं के मुताबिक योग करने से उनके जीवन में कई सकारात्मक सुधार आए हैं।

ज्योतिरादित्य का उदय, हाशिए पर जाती यशोधरा और वसुंधरा

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू होने के बावजूद यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। यशोधरा वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में मंत्री हैं। वो पहले ही अपने अनिश्चित पोस्ट-कोविड स्वास्थ्य के कारण चुनावी राजनीति से बाहर हो चुकी हैं। हालाँकि, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पिछले छह महीनों से वह नियमित रूप से सभी बैठकों में शामिल हुई हैं, दौरों पर गई हैं और नियमित काम कर रही हैं।

राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी बाधाओं को पार करने वाली वसुंधरा अब अस्तित्व की गंभीर लड़ाई में लगी हुई हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है और उनके कई समर्थक पार्टी टिकट हासिल करने में विफल रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा अपने आंतरिक विरोधियों से हिसाब चुकता करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन भाजपा की संभावित भारी जीत, जैसा कि कुछ सर्वेक्षणकर्ताओं और सर्वेक्षण एजेंसियों ने संकेत दिया है, उनकी संभावित राजनीतिक अप्रासंगिकता की ओर इशारा करती है। केंद्रीय मंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी ने राजस्थान के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका के लिए वसुंधरा के विकल्पों को प्रभावी रूप से सीमित कर दिया है। यशोधरा और वसुंधरा दोनों के करीबी सूत्र दुख और निराशा की भावना व्यक्त करते हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे, अम्मा साहेब, राजमाता विजयाराजे सिंधिया की बेटियों के रूप में वे भाजपा के प्रति वफादार और प्रतिबद्ध रहीं। विजयाराजे 1980 में भाजपा की संस्थापक सदस्य थीं और भाजपा के पहले अवतार भारतीय जनसंघ की एक प्रतिष्ठित हस्ती थीं। एक बड़ी हस्ती होने के बावजूद, उन्होंने अपने छह दशक लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कोई मंत्री पद या गवर्नर पद की मांग नहीं की। राजमाता जनसंघ और भाजपा के लिए भी एक प्रमुख धन संग्रहकर्ता थीं।

राजमाता ने दी इंदिरा लहर को चुनौती

वास्तव में 1967 में मध्य प्रदेश विधानसभा में राजमाता के प्रवेश ने घटनाओं के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ का मार्ग प्रशस्त किया जब 36 कांग्रेस विधायक विपक्षी खेमे में चले गए और राजमाता को मिश्रा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे का मास्टरमाइंड माना गया। मध्य भारत में पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी पार्टी संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) ने सरकार बनाई। हालाँकि, राजमाता ने मुख्यमंत्री का पद अस्वीकार कर दिया और अपने निर्णय के लिए कोई कारण नहीं बताया। 1980 के दशक में जब उनसे भाजपा का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा लहर को चुनौती दी, वह समय था जब कांग्रेस ने सदन में 352 सीटें हासिल कीं। जनसंघ ने ग्वालियर क्षेत्र में भिंड से राजमाता, गुना से उनके बेटे माधवराव और ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी तीन सीटें जीतीं। कांग्रेस की नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व में कट्टरता आ गई। इंदिरा ने एक कांग्रेस नेता को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के उन्मूलन के दौरान रूढ़िवादियों को एक महत्वपूर्ण झटका देकर असाधारण रा

प्रिवी पर्स 1947 में भारत के साथ एकीकरण के समझौते के तहत रियासतों के 565 शाही परिवारों को किया गया भुगतान था। हैदराबाद के निज़ाम सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें प्रति वर्ष 80 मिलियन रुपये से अधिक की कर-मुक्त पेंशन मिलती थी। सिंधिया को प्रति वर्ष 25 लाख रुपये मिलते थे। पहली बार, सिंधिया को अन्य राजघरानों के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ा। राजमाता ने अपने संस्मरणों में स्थिति में अचानक हुए इस बदलाव के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि पैसा कभी भी विचारणीय नहीं था। जब आप युवा होते हैं तो आप गरीबी या अन्य लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। वी पर्स की समाप्ति के बाद यह बदल गया और सिंधियाओं को महंगी खरीदारी करने से पहले दो बार सोचना पड़ा।विपरीत परिस्थितियों में खुद पर हंसने की क्षमता से धन्य, राजमाता अक्सर चुटकी लेती थीं। अब हम खरीदते नहीं हैं। हम विक्रेता हैं। ग्वालियर राजघराने के पास दर्जनों हाथी थे।

आजादी के बाद पहली बार बस्तर के 120 से अधिक गांवों में नए मतदान केंद्र, बैलेट से लाल आतंक को मिलेगा जवाब

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें बस्तर की 12 सीटें भी शामिल है। छत्तीसगढ़ चुनाव में वोटिंग की तैयारी को लेकर एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है। बस्तर में जिन 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। उनमें बस्तर के 120 गांव के निवासी आजादी के बाद पहली बार अपने गांव में मतदान करेंगे।

बस्तर के 120 से अधिक गांव में पहली बार वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। जब यहां के ग्रामीण पहली बार अपने गांव में मतदान दे सकेंगे। इस तरह यहां के गांव वाले बुलेट पर बैलेट के जरिए लोकतंत्र की जीत के गवाह बनेंगे।

गांव वाले मतदान को लेकर उत्साहित

इससे पहले यहां जब भी चुनाव होते थे। तब अधिकांश गांव के वोटर्स अपना वोट डालने के लिए दूसरे वोटिंग सेंटर पर जाते थे। जो इनके गांव से

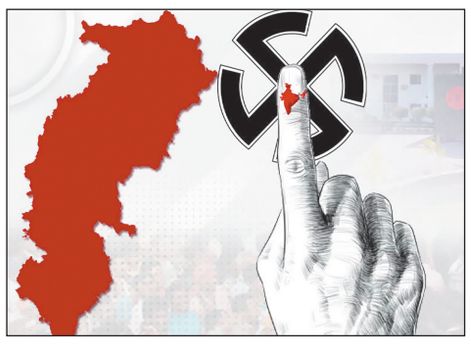

करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर रहता था। गांव वालों को पहाड़ियों और नालों को पार कर मतदान देने जाना पड़ता था। बस्तर के करीब 120 से अधिक गांवों में नक्सलियों का प्रभाव था। लेकिन माओवादियों के इस गढ़ में पहली बार नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जिससे गांव वाले मतदान को लेकर उत्साहित हैं। सात जिलों वाले बस्तर संभाग में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां सात नवंबर को वोटिंग होगी।

आईजी सुंदरराज पी ने कहा सात नवंबर को मतदान के लिए बस्तर क्षेत्र में 126 से अधिक नए मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से अधिकांश नए मतदान केंद्र अंदरूनी इलाकों में पूर्व नक्सली गढ़ वाले इलाकों में स्थित हैं।ये नए मतदान केंद्र बस्तर क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों को बुलेट पर बैलेट की जीत की कहानी सुनाएंगे। नए मतदान केंद्र बस्तर में बेहतर सुरक्षा की स्थिति और मजबूत होती लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकेत हैं। बस्तर में बीते पांच साल में 65 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। जिससे जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आया है।इसलिए यहां नए मतदान केंद्र को स्थापित करने में मदद मिली है।

इन इलाकों में बनाए गए मतदान केंद्र

कांकेर-15, अंतागढ़-12, भानुप्रतापपुर-5, कोंटा- 20, चित्रकोट-14, जगदलपुर- 4, कोंडागांव- 13, केशकाल-19, नारायणपुर- 9, दंतेवाड़ा- 8, बीजापुर- 6।

चांदामेटा में मतदान केंद्र बनने से लोग खुश

ऐसा ही एक गांव है चांदामेटा यहां पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है। जिससे गांव वाले काफी खुश हैं। चांदामेटा जगदलपुर निर्वाचन क्षेत्र के उन चार गांवों में से एक है। जहां पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

आदिवासी महिला पालो मरकाम ने कहा हमें वोट डालने के लिए 8 किलोमीटर दूर छिंदगुर जाना पड़ता था। वहां कोई सड़क नहीं थी। इसलिए कच्चे रास्ते से जाना पड़ता था। सड़क सिर्फ एक साल पहले बनाई गई थी। हम मतदान केंद्र पाकर बहुत खुश हैं। हमारे गांव में हम उसे वोट देंगे जो हमारे विकास के लिए काम करेगा।

चांदामेटा इलाका धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ ओडिशा की सीमा पर यह तुलसी डोंगरी की पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है।

श्याम कवासी ने कहा पहले हमारे गांव के कई मतदाताओं ने वोट डालने में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि मतदान केंद्र लगभग 8 किमी दूर था और सड़क की कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए यहां मतदान केंद्र बन जाने से काफी सहूलियत हो गई है। इस बार पूरा गांव लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए उत्साहित है।

चांदामेटा गांव में तेजी से हुआ विकास

बस्तर के कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि चांदामेटा गांव में मतदान केंद्र बनने से लोगों में खुशी है। यह गांव अब विकास की मुख्य धारा में जुड़ने की प्रक्रिया में है। यहां 432 लोगों की आबादी है। जिसमें 290 मतदाता हैं। इनमें 148 पुरुष, 142 महिलाएं हैं। जो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

पहले चरण में बस्तर संभाग के अलावा जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। उनमें मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुईखदान गंडई और कबीरधाम जिलों के आठ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

एक लाख का इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वर्राटू के तहत भैरमगढ़ एरिया कमेंटी अंर्तगत पिट्टेपाल सीएएनएम अध्यक्ष एक लाख के इनामी नक्सली राकेश कडियामी पिता मनकूराम कडियामी निवासी ग्राम कोंड़ापाल थाना मिरतुर ने आत्मसमर्पण का दिया है। आत्मसमर्पित नक्सली राकेश कडियामी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना, नक्सली बैनर, पोस्टर और पाम्पलेट लगाने एवं अन्य वारदातों में शामिल था। जिले में अब तक लोन वर्राटू अभियान के तहत 166 इनामी नक्सली सहित कुल 649 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

नक्सलियों ने ग्रामीणों व महिलाओं की बेदम पिटाई का लगाया आरोप

बीजापुर। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर एरिया कमेटी ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कर राज्य सरकार पर सूरजकुंड दमन योजना के नाम पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए, पर्चे में उल्लेख किया है कि 22 सितंबर को बीजापुर एसपी के निर्देश पर ग्राम कमकानार में पुलिस-सीआरपीएफ-डीआरजी के जवानों ने ग्रामीणों की बेदम पिटाई की, इसके साथ ही महिलाओं को भी पीटा गया, ग्रामीणों के दुपहिया वाहनों को क्षि पहुचाया गया। नक्सल संगठन ने इसे सरकार के इशारे पर आदिवासियों का दमन बताते हुए आम जनमानस, बुद्धिजीवियो से आगे आकर विरोध करने की अपील किया है।

टिकट कटने से नाराज चोपड़ा हो सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी

महासमुंद। भाजपा के कद्दावर नेता डा. विमल चोपड़ा को पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर उनकी नाराजगी उभरकर सामने आ गई है। पार्टी के प्रति वफादारी और अपने साफगोई व्यावहार से जनता के बीच में छवि बनाने वाले डा. विमल चोपड़ा ने टिकट काटे जाने पर पार्टी के नेताओं को जहां आड़े हाथों लिया वहीं उन्होंनें अपने समर्थकों के समक्ष एक-दो दिनों में स्थिति स्पष्ट करने का ऐलान कर दिया।

डा. विमल चोपड़ा महासमुंद की राजनीति में पिछले अनेक वर्षों से जबर्दस्त दखल बनाए हुए है। इससे पहले भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। महासमुंद से इस बार भाजपा ने डा. विमल चोपड़ा के स्थान पर योगेश्वर राजू सिन्हा पर दांव लगाया है और उसे प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद डा. विमल चोपड़ा पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे। आखिरकार उनकी नाराजगी अपने समर्थकों के साथ छलक आई। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका कोई पिताम्ह नहीं है और न ही वे किसी की लल्लो-चप्पो करते है, नतीजा यह है कि उनकी टिकट कांट दी गई। टिकट कांटे जाने का कारण जातिगत समीकरण को बताया गया है। डा. चोपड़ा ने कहा कि विडंबना यह है कि पार्टी एक ओर जाति समीकरण की दुहाई दे

रही है वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव से डा. रमन सिंह और खैरागढ़ से वीरेंद्र सिंह को टिकट दी है, याने मामा और भांजा दोनों चुनाव लड़ेंगे। अब जाति और परिवार कसौटी पर है।

डा. चोपड़ा के समर्थकों ने उनकी टिकट कांटे जाने पर पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाया था लेकिन उसका नतीजा सिफर रहा। डा. चोपड़ा ने अपने समर्थकों को हौसला बनाए रखने और सब्रता से रहने की नसीहत देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वे इस मामले में निर्णय लेंगे। डा. चोपड़ा द्वारा दिए गए इस आश्वासन का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों कमल को छोड़कर डा. चोपड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में महासमुंद के चुनावी समर में उतर सकते हैं।

सरगुजा में महिला वोटर्स बनेंगी नेताओं की भाग्यविधाता

सरगुजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार महिला वोटर्स का दबदबा रहने वाला है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों की माने तो इस बार प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है।महिलाओं को मतदान के लिए जागरुक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान चलाया था। जिसका असर भी देखने को मिला।आंकड़ों के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि आने वाले चुनाव में महिला वोटर्स कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगी।सरगुजा में भी महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। ऐसे में क्या है महिलाओं की सोच आईए जानते हैं।

बात करें साल 2018 के विधानसभा चुनाव की तो सरगुजा जिले में कुल 5 लाख 90 हजार मतदाता थे। इनमें से 2 लाख 94 हजार 13 पुरुष मतदाता और 2 लाख 96 हजार 430 महिला मतदाताओ की संख्या थी। पुरुष और महिला मतदाता की संख्या में महज 2417 महिला मतदाता अधिक थीं।

साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरगुजा जिले में कुल मतदाओं की संख्या 6 लाख 49 हजार 319 हो चुकी है। इनमें 3 लाख 21 हजार 113 पुरूष और 3 लाख 28 हजार 190 महिला मतदाताओं की संख्या है। इस बार के चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 7 हजार 77 ज्यादा हो चुकी है।

आंकड़ों पर गौर करें तो हम देखेंगे पिछले बार के चुनावी आंकड़ों की तुलना में इस बार महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2018 में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से 2417 अधिक थीं। वहीं अब 2023 में यह अंतर बढ़कर 7 हजार 77 हो चुका है। पिछले चुनाव के आंकड़ों से इस बार 4 हजा 6 सौ 60 महिलाएं अधिक हैं।

2023 में जिले की लुंड्रा विधानसभा में कुल 1 लाख 93 हजार 462 मतदाता हैं। इनमें 96 हजार 224 पुरूष और 97 हजार 235 महिला हैं। अम्बिकापुर विधानसभा में 1 लाख 25 हजार 935 पुरुष और 1 लाख 28 हजार 910 महिला, सीतापुर विधानसभा में 98 हजार 954 पुरूष और 1 लाख 2 हजार 45 महिला मतदाताओं की संख्या है। जिले में कुल 16 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जिनमें लुंड्रा में 3, अम्बिकापुर में 12 और सीतापुर में 16 थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या है।

मैं पार्टी के साथ हूं, मीडिया में जो बातें सामने आई है, मैं उसका खंडन करती हूं : ओजस्वी

दंतेवाड़ा। भाजपा ने दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से चैतराम अटामी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद स्वर्गीय भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मण्डावी ने नाराजगी जताई थी। जिसके बाद मीडिया में ओजस्वी मण्डावी के निर्दलीय चुनाव लडने की खबरें तक चल रही थी। अब इस मसले को लेकर भाजपा की प्रदेश मंत्री श्रीमती ओजस्वी मंडावी ने अपना बयान जारी किया है। श्रीमती मण्डावी ने कहा कि मैं भाजपा की पदाधिकारी हूं और पार्टी के साथ हूं, मीडिया के जरिए जो बातें सामने आई हैं मैं उसका खंडन करती हूं। उन्होने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और संगठन महामंत्री पवन साय से पार्टी संगठन के विषय में चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं को समझाया गया है। मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूं। मेरे निवास में कार्यकर्ता मिलने पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मिलना कोई गलत तो नहीं है। संगठन जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। इस दौरान जिला संगठन प्रभारी श्रीनिवास मददी भी वहां मौजूद

थे।

उल्लेखनिय है कि विधानसभा में टिकट को लेकर श्रीमती ओजस्वी मंडावी की बेटी दीपा मंडवी ने बीते दिनों एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि, मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही, उन्होंने भाजपा के लिए जान दे दी, उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए मां ओजस्वी मंडावी ने राजनीति में कदम रखा, पूरा परिवार भाजपा का सम्मान करता है, इसके बावजूद पापा बलिदान को भाजपा के पदाधिकारियों ने क्यों नजर अंदाज कर दिया? इसके बाद मचे बवाल को भाजपा शांत करवाने में सफल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनवा में बस्तर संभाग के 12 सीटों में से एक मात्र दंतेवाड़ा सीट से भाजपा के स्वर्गीय भीमा मंडावी ने जीत हासिल की थी। इसी बीच लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में उनकी जान चली गई थी। जिसके बाद उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी को उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया था।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नही रही भरथरी विधा की धनी अमृता बारले

भिलाई। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पूरे देश में भरथरी विधा को एक अलग पहचान दिलाने वाली भरथरी कलाकार अमृता बारले ने गुरुवार की देर शाम में भिलाई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थी और आईसीयू में भर्ती थी जहां डॉक्टरों की सतत निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। रात में ही उनके निधन का समाचार मिलते लोककला के क्षेत्र में दुख की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दोपहर में रिसाले मुक्तिधाम में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि अमृता बारले लोक कला के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध कलाकार थी जिसने भरथरी को छत्तीसगढ के साथ पूरे देश में एक अमिट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोककला के क्षेत्र में उनके इस योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हे मिनीमाता राज्य अलंकरण सम्मान से नवाज था। अमृता बारले का जन्म सन् 2 मई 1958 में छत्तीसगढ के ग्राम-बठेना, वि.ख. पाटन, जिला दुर्ग में हुआ था।

बिना अनुमति परिवहन कर रहे भाजपा की प्रचार सामग्री जप्त

कांकेर। दुर्गूकोंदल थाना क्षेत्र अंर्तगत अंतागढ़ से भाजपा के प्रत्याशी विक्रम उसेंडी के प्रचार के लिए सामग्री पखांजूर ले जाया जा रहा था। इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। जिला प्रशासन की स्पेशल टीम ने दुर्गूकोंदल के पास प्रचार सामग्री को जप्त कर लिया। ड्राइवर वाहन की अनुमति और सामग्री की रसीद नहीं दे सका, बिना अनुमति परिवहन कर रहे भाजपा की प्रचार सामग्री और वाहन को जप्त कर दुर्गूकोंदल थाने लाया गया। यह कार्रवाई एफएसटी की टीम प्रमुख एसपी कोसरे खंड शिक्षा अधिकारी ने की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीम जगह-जगह चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच कर रही है। प्रचार सामग्री अंतागढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विक्रमदेव उसेंडी का बताया जा रहा है, हालांकि उन्होंने इससे इकार करते हुए विक्रम उसेंडी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि प्रचार सामग्री पार्टी की तरफ से आती है।

नकली सोना गिरवी रखकर निजी बैंक से लिया लोन

कोरबा। कोरबा जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली सोना खपाने वाले मिर्जापुर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनका एक सदस्य कोरबा के नॉनबिर्रा का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरोह के कब्जे से नकली सोने से बना हुआ कुछ सामान जब्त किया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिर्जापुर जिले से संबंधित नकली सोना वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। बड़े कारनामे को अंजाम देने से पहले सीएसईबी चौकी पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को पकड़ लिया। मुनव्वर, अभिनव और उसका एक साथी इस मामले में शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने नकली सोने की चूड़ियां और अन्य सामान जब्त किया है। बस स्टैंड क्षेत्र में नए शिकार की खोज के दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया गया कि चांदी से बने सामान पर गोल्ड कोटिंग की गई थी। सीएसईबी चौकी प्रभारी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर टीपी नगर के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

बाइक सवार युवकों के ऊपर गिरा चावल से भरा ट्रक

जगदलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर गुरुवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक चावल बोरी से लदी होने के कारण अनियंत्रित होकर बाइक सवार दो युवकों के ऊपर जा पलटा। इस हादसे में दोनों युवकों की दबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। शवों को घंटो की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया की आनंद ढाबा के पास दो युवक एक बाइक में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि तभी आड़ावाल की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक जिसमे चावल भरे होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, इस घटना में दोनों युवक ट्रक के नीचे दब गए, घटना के तत्काल बाद ही आसपास के लोगों के साथ ही पुलिस टीम व नगर सेना की एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने पूरा चावल को वहां से हटाए और ट्रक के नीचे दबे दोनों युवकों को बाहर निकाला।

नोनी -जोहार कार्यक्रम में हुए युवोदय दुर्ग के दूत सम्मानित

दुर्ग। जिला प्रशासन और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जिले में जागरुकता कार्य हेतु युवोदय दुर्ग के दूत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन एवं अपर कलेक्टर व दुर्ग दूत कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री रोहित व्यास के दिशा निर्देश में दुर्ग दूत स्वयंसेवकों के द्वारा जिले में जागरुकता कार्य किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग, यूनिसेफ, अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 10 व 11 अक्टूबर को 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मानसिक तनाव के कारण एवं निदान की जानकारी दी गई इसके साथ खेल का भी आयोजन किया गया। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अभिनेत्री स्मृति कालरा नोनी जोहार कार्यक्रम में शामिल हुई एवं उनके द्वारा राज्य के सभी जिलों में किए जा रहे स्वयं सेवकों के कार्य की सराहना किया गया।

छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू होते ही जगदलपुर कांग्रेस में बढ़ी कलह!

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहा है। सात नवंबर को पहले चरण का मतदान है। इसके तहत बस्तर की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। शुक्रवार 13 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुक्रवार दोपहर तक जगदलपुर विधानसभा सीट से 2 और चित्रकोट विधानसभा सीट के लिए 2 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र लिया है।

बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में एक जगदलपुर विधानसभा सीट है, ये सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट में कांग्रेसियों में टिकट को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि शुक्रवार को

नामांकन पत्र लेने के लिए कांग्रेस नेता टीवी रवि कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। नामांकन पत्र लेने पहुंचे कांग्रेसी नेता टीवी रवि से मीडिया ने बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान टीवी रवि ने कहा कि, जगदलपुर विधानसभा क्रमांक 86 का आवदेन लेने के लिए आया हूं। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा कर रहा हूं। काफी समय से विधायक के टिकट के लिए दावेदारी कर रहा हूं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मेरा नाम अंतिम समय में हटाया गया था। उससे पहले 15 सालों तक विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के लिए काम किया हूं। बूथ से लेकर सेक्टर और सेक्टर से लेकर ब्लॉक लेवल और विधानसभा लेवल तक मैंने काम किया है। पार्टी के हित में अपना 10 साल लगाया।

कांग्रेस नेता टीवी रवि ने कहा कांग्रेस 2018 में सरकार में आई। लेकिन मुझे कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई। शायद पार्टी को लगता है कि मैं पार्टी का एक नागवारा बेटा हूं। जगदलपुर की जनता चाहती है कि वे उनके बीच में रहे। इसीलिए फॉर्म लेने आये हूं। अगर कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लडूंगा। ,

बता दें कि टीवी रवि के नामांकन पत्र लेने से ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं मिलने पर वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते है। इससे साफ है कि लोकल स्तर पर कई नेता टिकट की आस में हैं। ये नेता टिकट न मिलने पर नाराज हैं। इनकी नाराजगी का खामियाजा आने वाले दिनों में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।

रूठों को मनाने में जुटी भाजपा, चार मंडलों के निष्कासित कार्यकर्ताओं का निष्कासन आदेश रद्द

बालोद। भारतीय जनता पार्टी ने बालोद जिले के चार मंडलों से निष्कासित हुए 17 कार्यकर्ताओं का निष्कासन समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बालोद जिले से तीन विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की है जिसके बाद से यहां पर अब भाजपा रूठे और दूर हो चुके कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में निष्कासन निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। इनमें से ज्यादातर पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने वाले लोग शामिल हैं।

भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने सभी 17 कार्यकर्ताओं का निष्कासन बहाली आदेश जारी किया है। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने सभी का निष्काशन रद्द किया है।

जारी आदेश के अनुसार बालोद शहर मंडल से यूसूफ खान ,असीम दीवान, राजेश सोनी, अर्जुंदा मंडल से लीलेश्वर ठाकुर, चंद्रिका देवांगन, योगेश देवांगन,

किर्ति उइके, शत्रुघन यादव ,नेमिन यादव, संतोषी यादव, पोषण यादव ,डौंडी लोहार मंडल से प्रेमचंद भंसाली दल्ली राजहरामंडल मंडल से संतोष देवांगन, टी ज्योति, कुमारी रावटे, रमणी बाध, दीपिका सपहा का पार्टी में पुनः बहाली हुई यह जानकारी जिला भाजपा उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी राकेश यादव ने दी है।

संक्षिप्त समाचार

नांदगांव, डोंगरगांव व मोहला मानपुर के संकल्प शिवर में आज शामिल होंगे भूपेश

राजनांदगांव। नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो जाने के बाद भाजपा - कांग्रेस के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी ताकत झोंकने में जुट गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजनांदगांव, डोंगरगांव और मोहला-मानपुर में आयोजित संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरेंगे जिसकी तैयारियां अंतिम चरणों में है। तीनों विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र के असहयोगात्मक रवैये और भाजपा की जनविरोधी सोंच को लेकर जनता के बीच जाएंगे।

15 साल बनाम 5, कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर, बहस के लिए चुनौती भी दी

रायपुर। कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा गुरुवार को रायपुर दौरे पर रहे। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा ने कांग्रेस सरकार की 5 साल की उपलब्धियां बताई और बीजेपी सरकार के 15 साल की नाकामियां भी गिनाई। खेड़ा ने कहा - प्रदेश में जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई है। साथ ही चुनौती दी कि, हम 15 साल बनाम 5 साल पर डिबेट करने के लिए भी तैयार हैं। पवन खेड़ा ने कहा - प्रदेश की जनता भूपेश सरकार को फिर से लाना चाहती है।

छत्तीसगढ़ व्यापमं की कई भर्ती परीक्षा स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके लिए प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस वजह से राज्य में व्यापमं ने कई सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल कई पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से इन भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह भर्ती परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से 15 अक्टूबर कई पदों पर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा स्थगित होने के संबंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा के आयोजन को लेकर निर्वाचन आयोग से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव के माध्यम से व्यापमं की ओर से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने पर इस परीक्षा की तारीख फिर से घोषित की जाएगी।

आप ने 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की

रायपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पवितार को देर रात 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। आप द्वारा सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट की गई सूची में अधिकतर उम्मीदवार जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं। पार्टी ने लिखा है, घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची आ गई है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। इस बार चलेगी झाड़ू। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अब तक वह कुल 33 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। राज्य में पार्टी के मीडिया विभाग के सदस्य अनुपम सिंह ने बताया कि पार्टी ने जिन उम्मीदवारों की सूची जारी की है उनमें ज्यादातर जिला इकाई के पदाधिकारी शामिल हैं। सूची के अनुसार, बैकुंठपुर से डॉक्टर आकाश जायसवाल, कटघोरा से चंद्रकांत डिक्सेना, लोरमी से मनभजन टंडन, मुंगेली (अजा) से दीपक पात्रे, जैजैपुर से दुर्गालाल केंवट, कसडोल से लेखराम साहू, गुंडरदेही से जसवंत सिन्हा, दुर्ग ग्रामीण से संजीत विश्वकर्मा, पंडरिया से चमेली कुर्रे, बस्तर (अजजा) से जगमोहन बघेल और जगदलपुर से नरेंद्र भवानी को उम्मीदवार बनाया गया है।

दुर्ग कलेक्टर ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विधानसभा निर्वाचन-2023 के तैयारियों के संबंध में नोडल अधिकारियों की अद्यतन कार्यों की पी.पी.टी. के माध्यम से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के तहत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्वाचन कार्यों के लिए निर्वाचन व्यय से संबंधित कार्य मतदान दलों के लिए सामग्रियां, डाक मतपत्र की व्यवस्था, अनुमति, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन प्लान, मतदान दल रूट चार्ट, चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने, ई.व्ही.एम. एवं वी.वी.पैड, रेण्डमाइजेशन एवं कमिशनिंग कार्य, मतदान केन्द्रों की वेब कॉस्टिंग, सी-विजिल में दर्ज शिकायतें, मतदान केन्द्रों में निःशक्त सहायता केन्द्र, वाहन व्यवस्था, मतपत्र छपाई, विडियोग्राफी, प्रशिक्षण प्रबंधन, स्वीप कार्यक्रम, एम.सी.सी., बैलेट पोस्टल पेपर आदि की जानकारी ली। उन्होंने मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति की सुचारू संचालन व निर्वाचन प्रेक्षकों की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, जिला पंचायत सी.ई.ओ. अश्वनी देवांगन, दुर्ग नगर निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, रिसाली नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन, अपर कलेक्टर गोकुल रावटे आदि उपस्थित थे।

16 को राजनांदगांव जिले के सभी भाजपा प्रत्याशी करेंगे नामांकन जमा

■ **भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन, 15 को रमन का जन्मदिन, शाह होंगे शामिल**

राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गई है। राजनांदगांव जिले में सभी भाजपा प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए 16 अक्टूबर को एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। चूंकि 15 अक्टूबर को डा. रमन सिंह जन्मदिन है और इसी बहाने पार्टी अपनी जनाधार का प्रदर्शन करते ताकत दिखाएगी और राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल में सभा की तैयारी की जा रही है।

नामांकन की प्रक्रिया शुरु होने के बाद भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव-प्रचार में जोरशोर से जुट गए है और 16 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के सभी अधिकृत प्रत्याशी डोंगरगांव से भरत वर्मा, खुज्जी से गीता साहू, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर और राजनांदगांव से रमन सिंह एक साथ नामांकन जमा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के नामांकन दाखिले के समय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे और वे नामांकन दाखिले से पहले राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे।

शुक्रवार से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। 20 अक्टूबर तक नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने विधानसभा वार रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर दिए हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा के लिए एसडीएम गिरीश रामटेके निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा के लिए नामांकन न्यायालय नजूल अधिकारी के कक्ष क्र. 31 में जमा होंगे। राजनांदगांव विधानसभा के लिए कलेक्टोरेट के न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्र. 2 में नाम निर्देशन कक्ष बनाया गया है वहां एसडीएम अरुण वर्मा नामांकन प्राप्त करेंगे। इसी तरह डोंगरगांव विस के लिए न्यायालय भाड़ा नियंत्रण अधिकारी कक्ष क्र. 50 में एसडीएम अश्वन कुमार पुशाम को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। खुज्जी विस के लिए कलेक्टोरेट के न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्र. 30 में नाम-निर्देशन कक्ष बनाया गया है। अपर कलेक्टर इंदिरा देहारी खुज्जी विस क्षेत्र के राजनीतिक दलों का पर्चा प्राप्त करेंगी। सभी विस में निर्वाचन अधिकारियों के साथ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं।

भाजपा से बगावत कर राजेश ने दाखिल किया नामांकन

राजनांदगांव। नामांकन दाखिले के पहले ही दिन भाजपा में बगावत का पहला मामला सामने आया है जब आरक्षित डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में भारी समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। बागी होकर अब वे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी विनोद खांडेकर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बौद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर ने स्थानीय स्टेट हाईस्कूल में हजारों समर्थकों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान घुमका के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश यादव भी श्यामकर के पक्ष में खड़े दिखाई दिए।

भूपेश को देखकर जोगी की याद आती है: रविशंकर प्रसाद

रायपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ की तीन विधानसभा क्षेत्र का नब्ज टटोलने व असंतोष को कम करने आज रायपुर पहुंचे है। इस बीच उन्होंने कहा कि मुझे भूपेश बघेल को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याद आती है। उस समय क्या आतंक होता था? भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था।

मुख्यमंत्री के कैंडी क्रश वाले मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, भूपेश बाबू आपको कैंडी क्रश और गेमिंग एप से प्यार क्यों है? पता चला कि यहां महादेव एप चल रहा है। अब समझ में आया कि भूपेश बघेल को कैंडी क्रश क्यों पसंद है। भूपेश भ्रष्टाचार में सब पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से दो कलेक्टर जेल में है। उपसचिव भी जेल में है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार भी पारदर्शी है। यहां शराब घोटाला हो रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा, भूपेश यूपीए के घोटालों से सीख लीजिए। मनमोहन सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट में कोल घोटाला पर पिटिशन दायर की है। हमारी सरकार बनने वाली है। भ्रष्टाचार पर छोड़ेंगे नहीं। यहां छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती में घोटाला हो रहा है। हम घोटाले एक्सपोज कर चुके हैं। अब कार्रवाई करेंगे।

वह प्रदेश की तीन विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके भाजपा नेताओं के साथ चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक रविशंकर प्रसाद धरसींवा, आरंग और अभनपुर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जाहिर है इन्ही तीन सीटों पर अब तक सबसे ज्यादा असहमति के हालात नजर आये है।

भाजपा आरोप लगाने से पहले ईडी से पूछकर आएं: मुख्यमंत्री

■ **भूपेश बघेल ने दी भाजपा नेताओं को नसीहत**

रायपुर। पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा मीडिया के समक्ष दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिना किसी जानकारी के दिल्ली से आकर भाजपा के नेता उल्टी-सीधा बयान दे रहे है। मुख्यमंत्री ने सपाट शब्दों में कहा कि यदि भाजपा के नेताओं को महादेव ऐप के बारे में बोलना ही है तो सबसे पहले वे ईडी से जाकर पूछे लें कि जांच किसने शुरु की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु की और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया, इसी आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया है और रविशंकर इस मामले में हमारे से ही सवाल कर रहे है यह बड़ी हास्यास्पद बात है।

मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा दिल्ली से अपने कथित दिग्गजों को बुला रही है और छत्तीसगढ़ के बारे में उल-जलूल बयान दिलवा रही है। वे बिना जानकारी अगड़म बगड़म कुछ भी बोले जा रहे हैं. अरे भैया महादेव ऐप के बारे में बोलना है तो पहले अपनी ईडी से तो पूछ लो कि जांच किसने शुरु की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करके जांच शुरु की. सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया. इसी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया और अब आप हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं? सवाल हमारे पास भी हैं. केंद्र में भाजपा की सरकार है तो स्पोर्ट्स चैनलों और सोशल मीडिया पर दिन-रात विज्ञापनों के ज़रिए युवाओं को सट्टे की लत लगाने वाले जो अनगिनत गेम चल रहे हैं उन्हें सरकार क्यों नहीं रोक रही है? उन पर सरकार कानूनी पाबंदी क्यों नहीं लगाती?

भाजपा नेता ये बता दें कि आपने इस ऑनलाइन सट्टे पर रोक लगाने की जगह इस पर जीएसटी किस मंशा से लगाया? युवाओं में सट्टे की लत लग रही है. मुझसे सैकड़ों अभिभावकों ने आकर शिकायत की है। कुल मिलाकर जीएसटी चाहिए, तो देश के करोड़ों युवाओं को सट्टे में धकेलोगे? इस पर जवाब दे दें भाजपा के नेता, फिर हमसे सवाल पूछें।

प्रत्याशी की घोषणा पर कांग्रेस-भाजपा में वार-पलटवार

रायपुर। विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। दो चरणों में होने वाली वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को छोड़कर अभी किसी दल ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। लेकिन, वार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, वहां आपस में सिरफुटव्वल चल रहा है। वहीं, बीजेपी ने कहा है कि चुनाव के लिए मैदान सजकर तैयार है, लेकिन कांग्रेस को 'खिलाड़ी' (उम्मीदवार) ही नहीं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट करके कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार पर तंज भी कसा है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह चरम पर है। यही वजह है कि पार्टी ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन पांच सीट पर प्रत्याशी घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर कोई खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान रहा है। डॉ रमन सिंह अपने आप

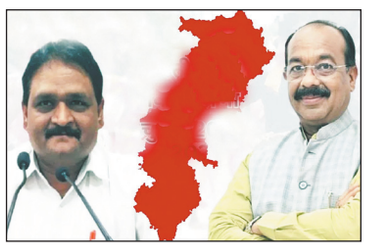

को सीएम मान रहे हैं, तो अरुण साव खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को पता है कि जनता उसे पसंद नहीं करती। एक बार भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 75 से अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी।

नवरात्र के पहले दिन होगी कांग्रेस कैंडिडेट्स की घोषणा

सुशील आनंद शुक्ला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने पितृपक्ष में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के लिए भी छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ लिया। कहा कि सनातन धर्म की बात करने वाले ये भूल गए कि सनातन धर्म में पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो दिन बाद हमारे उम्मीदवारों की भी सूची जारी हो जाएगी।

डॉ रमन सिंह के नामांकन में आएंगे अमित शाह

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। इसलिए बाहर से नेताओं को यहां प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद डॉ रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि राजनांदगांव में डॉ रमन सिंह काफी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि इस बार वह इस सीट से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वे बाहर से नेताओं को बुला रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं की लोकप्रियता नहीं रह गई है।

कांग्रेस में 40 सीटों पर नाम तय?

रायपुर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार है. केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस ने 20 सीटों पर अपना नाम लगभग तय कर लिया है. बता दें कि अब तक कांग्रेस पार्टी के 40 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं.

बताया जा रहा कि पहले चरण के 20 सीटों के बाद दूसरे चरण के सीटों पर प्रत्याशी तय किए. दूसरे चरण के 70 में से 20 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए हैं. पाटन से भूपेश बघेल, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, सक्ती से डॉ. चरणदास महंत, दुर्ग ग्रामीण या बेमेतरा से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविन्द्र चौबे, आरंग से डॉ. शिवकुमार डहरिया का नाम लगभग तय है.

ये हैं संभावित प्रत्याशियों के नाम

- पाटन से भूपेश बघेल
- अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव
- सक्ती से डॉ. चरणदास महंत
- दुर्ग ग्रामीण या बेमेतरा से ताम्रध्वज साहू
- साजा से रविन्द्र चौबे

- आरंग से डॉ. शिवकुमार डहरिया
- डौंडीलोहारा से अनिला भेंड़िया
- सीतापुर से अमरजीत भगत
- कोरबा से जय सिंह अग्रवाल
- खरसिया से उमेश पटेल
- अहिवारा या नवागढ़ से गुरु रूद्रकुमार
- राजिम से अमितेश शुक्ल
- दुर्ग शहर से अरुण वोरा
- रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय
- रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा
- बिलासपुर से शैलेष पाण्डेय
- भरतपुर सोनहत से गुलाब कमरो
- धरसींवा से अनिता योगेंद्र शर्मा
- कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर
- जांजगीर से मोतीलाल देवांगन या
- महंत रामसुंदर दास
- मोहम्मद अकबर, कवर्धा,
- कवासी लखमा, कोंटा,
- मोहन मरकाम ,कोंडागांव
- दीपक बैज, चित्रकोट
- संतराम नेताम, केशकाल
- देवती कर्मा, दंतेवाड़ा
- छन्नी साहू , खुज्जी,
- दलेश्वर साहू , डोंगरगांव
- वीरेंद्र मसिया / तेज कुंवर नेताम, मोहला मानपुर
- सावित्री मांडवी, भानुप्रतापपुर
- खैरागढ़ से गिरवर जंघेल / यशोदा वर्मा
- डोंगरगढ़ से थानेश्वर पटेल या भुवनेश्वर बघेल
- बस्तर से लखेश्वर बघेल
- जगदलपुर से राजीव शर्मा
- अंतागढ़ से रूप सिंह पोटाई
- कांकेर से शंकर धुर्वा
- पंडरिया से नीलू चंद्रवंशी / अर्जुन तिवारी
- बीजापुर से विक्रम मंडावी
- नारायनपुर से रजनू नेताम / चंदन कश्यप
- राजनांदगांव से हेमा देशमुख / जितेंद्र मुदलियार

पोगो और कैंडी क्रशवालों को अब तक चुनावी मैदान के लिए खिलाड़ी नहीं मिल पाए : साव

टिकिट वितरण को लेकर कांग्रेस असमंजस में

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से पहले चरण के 20 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण के 20 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है वहीं कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है । ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, 2 दिनों से चल रहे कैंडी क्रश विवाद के साथ तंज कसा है।

अरुण साव ने सोशल मीडिया एक्स में तंज कसते हुए लिखा है- आज से पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो रही है..! उधर पोगो और कैंडी क्रशवालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए चुनावी मैदान के लिए..! तैयार हो जाओ भाई, डरो मत!

भाजपा अध्यक्ष साव ने कांग्रेस के स्लोगन हैं तैयार हम पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उठे सवाल का भी करारा जवाब देते हुए लिखा है तैयार हो जाओ भाई डरो मत।

पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 07 नवंबर को मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की आठ सीट शामिल हैं। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है, उनमें भाजपा ने सभी सीटों प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को घोषित हो सकती है। पहले चरण में 20 सीटों पर 39 लाख 23 हजार मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

बेलतरा सीट को लेकर धर्मसंकट में भाजपा, ब्राम्हण समाज टिकट के लिए अड़ा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। केवल पांच सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। बिलासपुर की बात करें, तो जिसके 06 विधानसभा क्षेत्रों में से पांच में प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। मात्र बेलतरा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करना बचा है। बिलासपुर का ब्राम्हण समाज अपने लिए जिले की बची हुई एक सीट पर टिकट की मांग कर रहा है।

भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में 65 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद कहीं खुशी, तो कहीं से नाराजगी सामने आ रही है। कई सामाज अपने व्यक्ति के लिए टिकट मांग रहे हैं। बिलासपुर में ब्राम्हण समाज अपने समाज के किसी भी एक व्यक्ति को बेलतरा विधानसभा सीट से टिकट देने की मांग कर रहा है। ब्राम्हण समाज का प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को ज्ञापन भी सौंपा है। ब्राम्हण समाज ने पहले जिले के 6 में से किसी भी एक सीट पर टिकट देने की मांग की थी, लेकिन 5 सीट पर

प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब बची एक मात्र सीट बेलतरा के लिए टिकट की मांग की जा रही है।

ज्योतिन्द्र उपाध्याय ने कहा बिलासपुर संभाग में लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। चुनावों में निर्णायक भूमिका ब्राह्मणों की रहती है। भाजपा के सूची में एक भी ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी का नाम नहीं है, जिससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। अगर ब्राम्हण समाज के व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया, तो वो वोटिंग करने के लिए विचार करेंगे।

ब्राह्मण समाज का वोट हो सकता है निर्णायक- बिलासपुर संभाग, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। जिले में लगभग सवा लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। बिलासपुर विधानसभा में 40 हजार, बेलतरा विधानसभा में 20 हजार की आबादी ब्राह्मण समाज की है। ब्राह्मण समाज के वोटरों की संख्या इतनी है कि किसी भी पार्टी के लिए उनका वोट निर्णायक हो सकता है। यही वजह है कि ब्राह्मण समाज अपने समाज के लिए जिले से किसी एक विधानसभा में टिकट की मांग कर रहा था। ऐसे में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देने से बीजेपी को उनकी नाराजगी नुकसान पहुंचा सकती है। जिसके चलते अभी तक इस एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है।

बेलतरा विधानसभा सीट का गणित- बेलतरा विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की सीट है। यहां ओबीसी मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। ओबीसी के बाद एससी समाज की संख्या भी अच्छी खासी है। यहां ओबीसी मतदाताओं की संख्या लगभग 33 166 फीसदी है, तो एससी मतदाता 28 फीसदी हैं। अनुसूचित जनजाति 2 फीसदी और जनरल मतदाता 36 134 फीसदी हैं। इनमें ठाकुर, ब्राम्हण, यादव, सतनामी, साहू, कौशिक और कुछ संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं। बेलतरा में पार्टियों का फोकस साहू, कौशिक, ब्राम्हण और एससी समाज पर अधिक रहता है।

बेलतरा विधानसभा में कितने हैं मतदाता- बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या 2 लाख 35 हजार 671 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 19 हजार 694 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 15 हजार 977 है। यानि कि इस विधानसभा सीट पर महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर ही है। यह आंकड़े मार्च 2023 तक के हैं।

बेलतरा विधानसभा है भाजपा का गढ़- बेलतरा विधानसभा सीट में सामान्य वर्ग के लोग ज्यादा हैं। यहां से लगातार पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान दो बार और अविभाजित सीपत विधानसभा से एक बार जीत दर्ज कर चुके हैं। बद्रीधर दीवान लगातार तीन बार भाजपा से जीत दर्ज कर चुके हैं। अब यहां भाजपा के ही रजनीश सिंह विधायक हैं। जिनकी मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ रही है। सामान्य वर्ग की बहुलता वाले बेलतरा विधानसभा में अब तक कांग्रेस ओबीसी वर्ग का ही उम्मीदवार उतारती है, जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और वो हारते ही रहे।

भाजपा पर भारी पड़ेगा विपक्ष का जातिवाद ?

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में हिन्दुत्व के घोड़े पर सवार होकर विजय पताका फहराने का सपना पाले हुए है। यह वही हिन्दुत्व है जिसको बीजेपी और आरएसएस ने 80-90 के दशक में अयोध्या में हिन्दुओं के कण-कण में विराजमान प्रभु श्री राम लला के मंदिर निर्माण की सौगंध खाकर कांग्रेस के खिलाफ 'धार' दी थी। तब से आज तक हिन्दुत्व के सहारे बीजेपी का विस्तार होता गया और कांग्रेस सिकुड़ती गई। कांग्रेस की कमी को पूरा करने के लिए कई क्षेत्रीय क्षत्रपों ने विभिन्न राज्यों में अपना राजनैतिक विस्तार कर लिया। इसमें बिहार में लालू यादव-नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह-मायावती जैसे पिछड़े और दलित नेताओं का उभार हुआ। इन्होंने कुछ वर्षों में ही बीजेपी की हिन्दुत्व वाली राजनीति की हवा निकाल कर रख दी। कोई पिछड़ों और मुसलमान वोट बैंक के तो कोई दलित-मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ा। यह सब अपने-अपने राज्यों में मुख्यमंत्री तक बने। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1992 में कथित बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस के बाद हिन्दुत्व की राजनीति हाशिये पर जाना शुरू हो गई थी, वहीं अगड़े-पिछड़ों-दलित और मुसलमान वोट बैंक की राजनीति आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। जातिवाद के नाम पर लोग अलग-अलग दलों के लिए वोट करने लगे थे। पिछड़े मुलायम के साथ चले गए और दलित मायावती के साथ हो लिए। भाजपा मात्र अगड़ों की पार्टी बनकर रह गई, जिनकी समाज में भागीदारी काफी कम थी। भाजपा और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थीं, लेकिन कांग्रेस का उतना बुरा हाल नहीं था, जितना बीजेपी का हो रहा था। इसीलिए कांग्रेस 2014 तक केन्द्र की सत्ता में रही या इर्दगिर्द घूमती रही। यह सिलसिला 2014 में केन्द्र की राजनीति में मोदी युग की शुरुआत के साथ थम गया। मोदी का सिक्का ऐसा चला कि जातीय राजनीति और उसके पुरोधा दोनों हाशिये पर चले गए, लेकिन जातिवादी राजनीति करने वाले कहीं न कहीं अपने दिल में यह मंसूबा जरूर पाले रहे कि एक न एक दिन उनकी जातिवादी हांडी फिर राजनीति के चूल्हें पर चढ़ेगी। इसीलिए इसके प्रयास भी होते रहे। इसके लिए गैर बीजेपी दलों ने जातिगत जनगणना कराये जाने की मांग को हवा देना शुरू कर दिया, इसमें सबसे खास बात यह रही कि जिस कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता और स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी जातिवादी जनगणना को देश के लिए खतरा बताते थे, उसी खतरे को राहुल गांधी ने कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का हथियार बना लिया है। कौन सही था, कौन गलत यह तो समय बतायेगा, परंतु अगले वर्ष होने वाले लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष को लग रहा है कि वह जातिगत जनगणना की सियासत के सहारे बीजेपी को पटकनी दे देगा, वह एक घातक सोच है, भले ही इससे इंडिया गठबंधन को सत्ता हासिल हो जाये, मगर देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से जातिगत जनगणना की आड़ में कुछ लोग सनातन धर्म को शर्मसार कर रहे हैं, वह इसकी बानगी भर है। यह सच हो सकता है कि सनातन धर्म में ऊंच-नीच का भेदभाव दिखाई देता हो, लेकिन यह सनातन धर्म नहीं, हिन्दू समाज की कमी है। वर्ना उन धर्मों से तो सनातन धर्म काफी सही है जहां धर्म की आड़ में खून की होली खेली जाती है। आतंकवाद को पालापोसा जाता है, लेकिन वोट बैंक की सियासत के चलते इस पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है।? बेहद शर्मनाक है कि जहां भाजपा अपने सबसे बड़े और धारदार सियासी हथियार हिंदुत्व को फिर से आजमा कर कमंडल राजनीति को गरम करने में लगी है, तो वहीं उसकी काट के लिए राजद, जद (यू) और समाजवादी पार्टी हिंदू ध्रुवीकरण की काट के लिए जातीय जनगणना और रामचरित मानस विवाद के जरिए पिछड़ों के ध्रुवीकरण की मंडल राजनीति का दांव खेलने में जुट गए हैं।

घोटालों को दबाने जाति जनगणना

आनंद कुमार

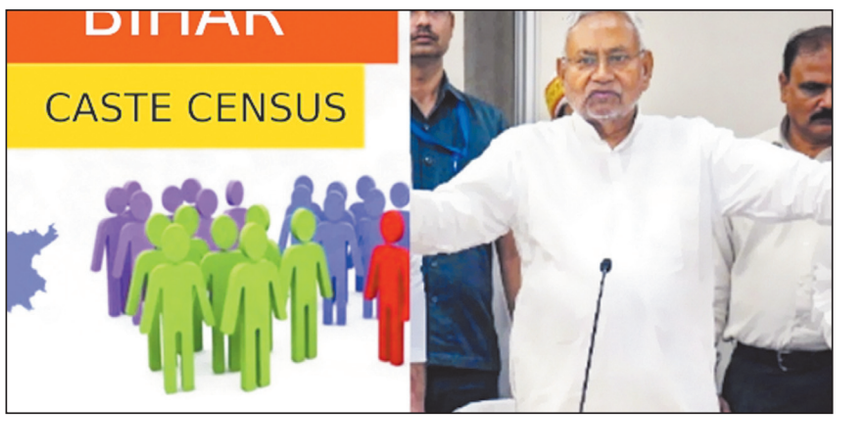

बिहार में जाति जनगणना के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों में जानबूझकर कुछ जातियों को कमतर दिखाने का आरोप तो लग ही रहा है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का पांसा अपने शासन काल में हुए घोटालों को छिपाने के लिए फेंका है।

हजार करोड़ का सृजन घोटाला- नीतीश शासन की बहती गंगा मानकर जिन घोटालों में हाथ धोये गए हैं, उनमें से सबसे चर्चित सृजन घोटाला था। हजार करोड़ के इस घोटाले का नाम सृजन घोटाला इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार के भागलपुर जिले में सृजन महिला सहयोग समिति नाम की एक संस्था इससे जुड़ी थी। मनोरमा देवी नाम की एक महिला ये एनजीओ चलाती थी। सरकार से जो फण्ड इन्हें काम करने के लिए मिलते थे, उसे बीच में ही गायब करके दूसरे बैंक खातों में डाल दिया जाता था। जो सूद मिलता उससे दिखाने के लिए छोटा-मोटा कुछ-कुछ काम जैसा आयोजन इत्यादि किया जाता और करोड़ों का मूलधन आराम से सूद कमाने के लिए रख लिया जाता।

ये कार्यक्रम सात वर्षों तक 2007 से 2014 के बीच चलता रहा। इस दौरान मनोरमा देवी ने जो अन्य कारनामे किये उनमें 2003 में 24000 स्क्वायर फीट की जमीन 30 वर्षों के लिए लीज पर ली, जिसके लिए उन्होंने 2400 रुपये की भारी भरकम रकम अदा की थी! शुरूआती पुलिस प्राथमिकियों की मानें तो ये घोटाला 16 दिसम्बर 2003 से 31 जुलाई 2017 तक चलता रहा जिसमें सरकारी खजाने से अवैध निकासी होती रही।

तटबंध घोटाला- एक सामाजिक कार्यकर्त्ता शिवेश भारती ने पटना उच्च न्यायलय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि 3608 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी सीतामढ़ी में तटबंधों की हालत खस्ता है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच करने के आदेश दिए। इस मामले के सामने आने पर राजद के नेताओं ने (जो कि उस वक्त विपक्ष में थे) जमकर बवाल काटा। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले के सजायाफ्ता अपराधी लालू यादव तक कहने लगे कि बिहार में घोटालों की सेल लगी है - एक पर एक मुफ्त ले लो!

अभी का हाल देखें तो चाचा-भतीजा यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार चला रहे हैं।घोटाले का क्या हुआ पता नहीं। वैसे इस मामले में सच्चाई बाहर आने की कितनी संभावना थी, इसका अनुमान आप इस बात से लगाइए कि जांच जल संसाधन विभाग के कर्मियों पर होनी थी और अदालत के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग के ही 72 कर्मचारी इस घोटाले की जांच कर रहे थे! उस दौर के राजद नेताओं के बयानों की मानें तो ये घोटाला भी 11,000 करोड़ रुपये से ऊपर का था।

महादलित घोटाला- इस घोटाले का नाम महादलित घोटाला इसलिए पड़ा क्योंकि नीतीश बाबु की सुशासन सरकार ने दलितों में भी कुछ जातियों को चुनकर महादलित घोषित कर दिया था। महादलितों को अंग्रेजी बोलना और कंप्यूटर चलाना सिखाने के नाम पर 2010 से 2016 के बीच घोटाला किया गया। इस मामले में राज्य की विजिलेंस ब्यूरो ने 23 अक्टूबर 2017 को एस.एम. राजू पर एफआईआर दर्ज की। बाद में एक दूसरी एफआईआर हुई जिसमें कई आरोपी थे।

ब्रिटिश लिंगुआ नाम की एक संस्था जो पटना में खासी प्रसिद्ध है, उसके निदेशक बीरबल झा, उस दौर के मिशन निदेशक और रिटायर हो चुके आईएएस अफसर राघवेन्द्र झा और राजनारायण लाल, रामाशीष पासवान, मिशन के तब के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा (जो कि अब रिटायर हैं), मिशन के कोऑर्डिनेटर शशि भूषण सिंह, सहायक निदेशक हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और बिरेन्द्र चौधरी और तब के मिशन के स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर देबजानी कार को भी बाद में एफआईआर में आरोपी बनाया गया।

विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक 2012-13 से लेकर 2015-16 के बीच ब्रिटिश लिंगुआ को 7.3 करोड़ रुपये दिए गए। उन्हें 40-40 छात्रों-छात्राओं के बैच को पढ़ाना था लेकिन जांच में पता चला कि जिन छात्र-छात्राओं का नाम एक बैच में था, वही नाम दूसरे कई बैच में भी थे! इस तरह बिना पढ़ाये ही महादलितों के नाम पर पैसे लिए जाते रहे। इस मामले की जांच भी अभी तक चल रही है।

टॉयलेट घोटाला- विचित्र नाम वाला ये घोटाला कहीं दूर नहीं हुआ था। सुशासन बाबु की सरकार के ठीक नाक के नीचे, राजधानी पटना से इस घोटाले की बदबू उठने लगी। पंद्रह करोड़ का ये घोटाला करने में ज्यादा समय भी नहीं लगाया गया था। केवल 1 मे से 16 जून 2016 के बीच पंद्रह करोड़ रुपये जो केंद्र की स्वच्छ भारत मिशन योजना के थे, वो गायब हो गए। तब के पटना के डीएम, संजय अग्रवाल ने पाया कि नियमों को ताक पर रखकर पैसे निकाले गए हैं तो उन्होंने जांच करवाई कि सचमुच शौचालय बने भी हैं या नहीं?

जांच में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिन्हा और पीएचईडी के लेखापाल बिटेश्वर प्रसाद ने मिलकर चार एनजीओ पकड़े जिनके जरिये पैसे की निकासी करनी थी। बिटेश्वर प्रसाद ने धड़ाधड़ 200 से अधिक चेक महीने-डेढ़ महीने में जारी कर डाले और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के एक सहायक प्रबंधक शिव कुमार झा ने इन चेकों की निकासी में मदद की। इस तरह गरीबों के लिए जो शौचालय कभी बने ही नहीं, उन्हें बनाने की रकम निकाल ली गयी। इस घोटाले की बू भी अभी तक आ रही है।

गंगा ब्रिज घोटाला- ये बिहार का सबसे नया ताजा घोटाला है जो तेजस्वी यादव का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इस घोटाले पर रोशनी डालने के लिए मनीष कश्यप का नाम लिया जाता है। मनीष कश्यप पर फिलहाल तमिलनाडु की पुलिस ने एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया है और दूसरे कई पुराने मामले खोदकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई भी लगी हुई है। गंगा नदी पर भागलपुर जिले में आगुवानी-सुल्तानगंज के बीच सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण हो रहा था। इस 3 किलोमीटर लम्बे पुल का निर्माण 2017 में शुरू हो गया था। पहली बार ये पुल 30 अप्रैल 2022 को टूटा था। उसके बाद यही पुल 5 जून 2023 को टूट गया। जब दूसरी बार ये पुल टूटा तब इसपर कथित रूप से आठ मजदूर थे और एक गार्ड था जो कि लापता है।

इस पुल को 2020 में ही बनकर पूरा हो जाना था और इसकी लागत थी 1710 करोड़ रुपये। नियत समय के तीन साल बाद भी ये पुल बनते-बनते ही टूट क्यों रहा है? कहा जाता है कि इससे पार्टी फण्ड में दस फीसदी यानि 171 करोड़ रुपये का कट जा रहा है। अब ब्रिज का क्या है? ब्रिज तो बनता और टूटता रहता है।

एक के बाद एक इतने घोटाले हाल के दौर के हैं जिनपर जवाब देना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो होगा। एक पुल गिरने पर ही जब सवाल हुए तो पूछने वाले पत्रकार को उठा कर जेल में फेंक दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बिहार में ये हाल है कि अख़बारों में जहरीली शराब से मौत भी नहीं लिखा जाता। आजकल छपता है कि मिलावटी पेय पीने से कोई अंधा हो गया तो किसी की जान चली गयी।

अब समस्या एक के बदले दो हो गयीं हैं। पहले सत्ताधारियों को केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटना था। अब एक तरफ जहाँ सिपाही भर्ती में घोटाला खुलकर सामने ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अत्यंत पिछड़ी जातियां भी प्रतिनिधित्व मांगने लगी हैं। राजद-जद(यू) गठबंधन के लिए रोज़े माफ़ करवाने गए थे, नमाज गले पड़ गयी वाली स्थिति हो गयी है। बाकी सबसे ताजा जांच जो पुलिस भर्ती में हुए घोटाले की होनी शुरू हुई है, उसकी आंच भी थमने वाली नहीं क्योंकि जिस पद पर बहाली में घोटाला सामने आया है, उस पद पर आवेदन देने वालों में भी तो 68त्न पिछड़ी जातियों के युवा होंगे।

तब इन घोटालों को दबाने और छिपाने के लिए जाति जनगणना का सहारा ले लिया तो क्या गलत किया? राजनीति में तो वैसे भी प्रचलित है कि जिस सवाल की जवाब न दे सको उस सवाल को ही बदल दो। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाकर यही किया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-15)

गतांक से आगे...

अन्त: पुर के प्राङ्गण में जिस तरह साध्वी पत्नी प्रसन्न रहती हैं, वैसे ही सहज क्रम में प्राप्त वस्तु में जब बुद्धि रमण करने लगती है, तभी वह स्वरूपानंद प्रदायी जीवन्मुक्त स्थिति कहलाती है।

समय एवं देश के अनुसार शास्त्रानुकूल आनन्दपूर्वक यथाशक्ति सत्संग में ही विचरण करते हुए इस मोक्षपथ के क्रम का तब तक ज्ञानीजन चिन्तन करते रहें, जब तक कि उन्हें आत्मिक विश्रान्ति न मिल जाये। सदृहस्थ हो अथवा संन्यासी, जो भी व्यक्ति तुरीयावस्था की विश्रान्ति से सम्पन्न है एवं इस संसार सागर से निवृत्त हो गया है, वह चाहे सांसारिक जीवन में व्यस्त रहे अथवा न रहे, उसे कोई भी कार्य करने या न करने से कोई मतलब नहीं है। उसे श्रुति स्मृति के भ्रमजाल में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह तो मन्दराचल से विहीन (शान्त) सागर की भाँति आत्म-स्थित रहते हुए सभी कुछ प्राप्त कर लेता है।

जब सभी के प्रति शुद्ध आत्मतत्त्व की अनुभूति की तदात्मक (एकत्व) वृत्ति का उदय हो जाता है, तब दिशा एवं काल में विस्तीर्ण हुआ सम्पूर्ण बाह्य जगत, चिद्रूपात्मक ही प्रतीत होता है। इस तरह आत्मा जहाँ जिस रूप में उल्लास को प्राप्त होता है, वहाँ शीघ्र ही उसी रूप में वह अवस्थित हो जाता है एवं तदनुरूप ही विराजमान हो जाता है।

जो भी कुछ स्थावर एवं जंगम दृश्यरूप यह सम्पूर्ण जगत् परिलक्षित होता है, वह प्रलय के समय में ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाता है, जैसे सुषुप्तावस्था में स्वप्न अदृश्य हो जाता है। यह आत्मा ब्रह्म (आदिकारण) रूप है, परब्रह्म परमेश्वर है। वह सत्यरूप है। ये समस्त संज्ञायें विद्वज्जन एवं महान् आत्माओं ने व्यवहार के लिए कल्पित की हैं। जैसे कङ्कण (हाथ का आभूषण) शब्द एवं उसका अर्थ स्वर्ण से अलग अस्तित्व नहीं रखता और कङ्कण से प्रतिष्ठित स्वर्ण कङ्कण से अलग अपना अस्तित्व नहीं रखता, ठीक वैसे ही जगत शब्द का तात्पर्य भी परब्रह्म ही होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उस अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर ने जगत् के रूप में यह इन्द्रजाल विस्तीर्ण किया है। द्रष्टा का दृश्य श्री सत्ता से अन्त: सम्बद्ध होना बन्ध कहा जाता है। दृश्य के वशीभूत होकर ही द्रष्टा बन्धन में पड़ता है और दृश्य के अभाव में ही वह मोक्ष प्राप्त करता है।

यह जगत, मेरा-तेरा रूप भाव वाली सृष्टि, दृश्य कहलाती है। इस संसार में प्रपञ्चरूपी इन्द्रजाल मन के द्वारा ही प्रबुद्ध होता है। जब तक मन की यह कल्पना समाप्त नहीं होती, तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता नहीं दिखलाई पड़ता। यह संसार स्वयंभू ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, अत: दृष्टिगोचर होने वाले इस विश्व को मनोमय ही समझना चाहिए। बाह्य अथवा अन्त:करण में कहीं पर भी यह मन सद्रूप में अवस्थित नहीं है।

क्रमश: ...

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस

अरविंद मिश्रा

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में ई-कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य पुन: उपयोग, वसूली और रीसाइक्लिंग दरों में वृद्धि करना है।

भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं लोगों के जीवन को आसान बना रही है। पर अर्थव्यवस्था का डिजिटल अवतार इलेक्ट्रॉनिक कचरे की शक्ल में एक नयी चुनौती लेकर आया है। घरों में इस्तेमाल होनेवाले कूलर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन जैसी वस्तुओं के अलावा मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल घड़ी तय समय के बाद ई-कचरा में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे पहले की भारत ई-कचरे का बड़ा डंपिंग ग्राउंड बन जाए, समय रहते इसके निस्तारण की व्यवस्था बनानी होगी।

ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में लगभग 53 16 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा दुनियाभर में उत्पन्न हुआ। इस दशक के अंत तक यह 74 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच जायेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें, तो 2021-22 में देश में 16 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न हुआ। इसमें मुश्किल से 30 प्रतिशत ई-कचरे का भी

निस्तारण नहीं हो पा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, ई-कचरा दूसरे प्रदूषक घटकों की अपेक्षा बेहद घातक है। इसमें सीसा, पारा, कैडमियम जैसे विषैले तत्व पाये जाते हैं, जो सांस की बीमारी और कैंसर पैदा करने की वजह बनते हैं। देश में एक अप्रैल, 2023 से ई-अपशिष्ट प्रबंधन के नये नियम लागू हैं। हालांकि, अभी इसका सफल क्रियान्वयन बाकी है। एक आम उपभोक्ता घर में खराब हो चुकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को अमूमन कबाड़ी वाले को देता है। पर पुनर्चक्रण इकाई तक ई-कचरे का बहुत कम हिस्सा पहुंचता है, क्योंकि देश में पुनर्चक्रण केंद्र की कमी है। महानगरों और राज्यों की राजधानी में भी पुनर्चक्रण संयंत्र गिने-चुने ही हैं।

ई-कचरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, बेहतर होगा कि ठोस और गीले कचरे की तरह ई-कचरा संग्रह की व्यवस्था हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार और स्थानीय निकाय के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक साजो-सामान बनाने और बेचने वाली कंपनियां भी इसके संग्रहण प्रक्रिया को मजबूती दें। ई-अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी संस्था करो संभव के संस्थापक, प्रांशु सिंघल के अनुसार, ई-कचरे में सोना, चांदी, निकेल, कोबाल्ट, पैलेडियम, प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं के अलावा कई हानिकारक तत्व भी होते हैं। वर्तमान पुनर्चक्रण व्यवस्था का पूरा जोर केवल महंगी धातुओं को प्राप्त करने पर है। इससे ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य धूमिल होंगे। बेहतर होगा कि ई-कचरे में मौजूद हानिकारक तत्वों को पर्यावरण को दूषित करने से रोका जाए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से सजावटी वस्तुएं बनाने के चलन पर भी रोक लगनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान के कचरे में तब्दील होने की अवधि को बढ़ाने के लिए वस्तुओं की डिजाइनिंग को टिकाऊ बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जितनी पर्यावरण अनुकूल होंगी, पुनर्चक्रण उतना ही आसान होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय राइट टू रिपेयर के जरिये इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पुन: प्रयोग (रियूज) को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए कंपनियों और ब्रांडों को उपभोक्ताओं के साथ वस्तुओं की मरम्मत से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करने को कहा गया है।

इजराइल अरब वार : एक ऐसा युद्ध जिसका कोई अंत नहीं

संजय तिवारी

शनिवार की सुबह इजराइल पर हमास के भीषण हमले के बाद इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो पहला संदेश जारी किया उसमें कहा हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम पर हमला हुआ है। न ही उन्होंने यह कहा कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके अर्थ बहुत गहरे हैं और इतिहास में हजार साल तक पीछे जाते हैं। इजराइल देश का नाम बाद में हुआ उसके पहले यह जैकब का उपनाम था। जैकब मतलब यहूदियों के पितामह माने जाने वाले इब्राहिम के पोते और इशाक के बेटे। जैकब ने जब जब स्वर्गदूतों के साथ कुश्ती लड़ी तो उन्हें यह नाम दिया गया इजराइल, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का योद्धा। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक जैकब के जो 12 बेटे हुए, उन्हीं से यहूदियों के 12 कबीले बने और सब अपने आप को इजराइल का वंशज यानी ईश्वर का योद्धा मानते हैं। इस्लामिक किताबों में इन्हीं की पहचान बनी इजराइल के तौर पर की जाती है।

इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की शुरुआत भी इस्लाम के उदय के साथ ही हो गयी। जो इस्लामिक किताबें लिखी गयीं उनमें %बनी इजराइल% को अल्लाह का दुश्मन घोषित किया गया और उनसे लड़ने का आदेश दिया गया। कुरान हो या इस्लामिक हदीसें उनमें इस्लाम के मानने वालों को बताया गया कि वो इजराइल की संतानों से श्रेष्ठ हैं। हदीसें लिखी गयीं कि कैसे उनके पैगंबर ने मदीना से इनका सफाया कर दिया था। इस्लामिक

किताबों के मुताबिक मदीना में उस समय तीन यहूदी कबीले थे। बनू कुनैजा, बनू कुरैजा और बनू नादिर। इसमें से बनू कुरैजा के सफाये का विस्तृत विवरण हदीस की प्रामाणिक पुस्तकों में दिया गया है। ऐसे में यहूदियों से लड़ाई करना मुसलमानों के लिए अपने ईमान पर अमल करना है। वो दुनिया भर में जहां होते हैं इजरायलियों को लानते भेजते हैं। मौका मिलते ही मारने का प्रयास भी करते हैं। जैसे हमास के हमले के बीच मिस्र में एक पुलिसवाले ने ही दो यहूदी टूरिस्टों को गोली मार दी। खुद हमास के मुजाहिदों ने इजराइल के भीतर घुसकर जिस तरह की बर्बरता दिखाई है उससे यहूदियों के प्रति उनकी नफरत साफ दिखाई देती है।

याद करिए 2008 का मुंबई पर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला। मुंबई हमले के दौरान यहूदी समुदाय के कॉफी हाउस लियोपोल्ड कैफे को भी निशाना बनाया गया था और आतंकियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी थी। मतलब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने जब मुंबई पर आतंकी हमले का प्लान बनाया तो उन्हें यह पता था कि मुंबई में कुछ यहूदी भी रहते हैं इसलिए उनके कॉफी हाउस को निशाना बनाया गया ताकि यहूदियों को मारकर सुन्नत पर अमल किया जा सके।

इसलिए हमास के ताजा हमले के बाद बेंजमिन नेतन्याहू ने बहुत चुनकर हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे शब्द का प्रयोग किया। यहूदी जानते हैं कि वो चाहें न चाहें उन्हें युद्धभूमि से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए नेतन्याहू ने साफ साफ हम युद्ध में हैं, शब्द का प्रयोग किया है। अब हर यहूदी यह समझ गया है जब तक धरती पर इस्लामिक किताबों पर ईमान लानेवाले मुसलमान हैं वो चाहें न चाहें उन्हें इस युद्ध में घसीटा जाता रहेगा। इसलिए 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य वाले फिलिस्तीन से अलग करके ब्रिटिश शासकों ने जब यहूदियों को अपना देश इजराइल दे दिया उसके बाद उन्होंने एक कौम के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में चुनौतियों का सामना करने की योजना पर काम शुरु किया। 1948 में एक देश के रूप में इजराइल को पा लेने के बाद यहूदियों ने समझ लिया कि वो एक ऐसे युद्ध में हैं जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। उन्हें इसी युद्ध में अपने आप को जिन्दा रखना है इसलिए न केवल आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से बल्कि सैन्य और सामरिक रूप से भी उन्होंने अपने आप को संगठित किया।

इसलिए 1967 में पहली बार यहूदियों ने किसी युद्ध में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। इस युद्ध में इजराइल की संतानों ने गाजा पट्टी, वेस्टबैंक, सिनाई और गोलान हाईट्स को कब्जे में ले लिया। इस युद्ध के बाद लगभग दस लाख अरब मुस्लिम यहूदियों के कब्जे में आ गये। इसके बाद 1995 में जो ओस्लो समझौता हुआ तो वेस्ट बैंक के तीन हिस्से कर दिये गये। एक हिस्सा वह जिस पर फिलिस्तीनियों का शासन है। एक हिस्सा वह जिस पर इजराइल का शासन है और एक हिस्सा वह जिस पर दोनों का संयुक्त शासन है। वेस्ट बैंक में 4.5 लाख यहूदी और लगभग 25 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। मेनलैण्ड इजराइल में 60 लाख यहूदी और 16 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वैसे तो वेस्टबैंक के इलाके में इजराइली और फिलिस्तीनियों के बीच रोजाना का संघर्ष रहता है लेकिन इस बार इजराइल के खिलाफ जो हमला गाजापट्टी की ओर से हुआ वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से हुआ जिसमें 1967 के बाद पहली बार इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की जड़ 1948 में नहीं है जब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने यहूदियों को इजराइल सौंपा था। इसकी जड़ें उससे अधिक गहरी हैं जो टेम्पल ऑन माउण्ट या फिर डोम ऑफ द रॉक में निहित हैं। वेस्टबैंक में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भले ही कल को गाजा पट्टी तक सिमट जाए लेकिन येरुसलेम पर जो इस्लामिक दावा है वह भला मुसलमान कैसे छोड़ देगा? अगर ओल्ड जेनेसिस (हिब्रू बाइबल) उसे किंग डेविड का शहर बता रहा है तो इस्लाम भी अपने पैगंबर के मेराज का सफर भी यहीं से करवा रहा है। बात अगर जमीन की हो तो एकबार को जीत हार से फैसला हो भी जाता है लेकिन यहां तो मसला मजहब और ईमान का है। इसलिए अगर बेंजामिन नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो निश्चित ही इसके लिए इजराइल की संतानों ने पीढियों के संघर्ष का खाका जरूर खींचा होगा। पच्चीस पचास साल में तो इस युद्ध का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है।

हिन्द स्वराज्य

सत्याग्रह-आत्मबल (भाग-6)

गतांक से आगे...

प्रश्न- आप जो कहते हैं उस पर से मुझे लगता है कि सत्याग्रह कमजोर आदमियों के लिए काफी काम का है। लेकिन जब वे बलवान् बन जायँ तब तो उन्हें तोप (हथियार) ही चलानी चाहिए।

उत्तर- यह तो आपने बड़े अज्ञान की बात कही। सत्याग्रह सबसे बड़ा-सर्वोपरि बल है। वह जब तोपबल से ज्यादा काम करता है, तो फिर कमजोरों का हथियार कैसे माना जायेगा? सत्याग्रह के लिए जो हिम्मत और बहादुरी चाहिए, वह तोप का बल रखने वाले के पास हो ही नहीं सकती। क्या आप यह मानते हैं कि डरपोक और कमजोर आदमी नापसन्द कानून को तोड़ सकेगा? एक्स्ट्रीमिस्ट तोपबल-पशुबल के हिमायती हैं। वे क्यों कानून को मानने की बात कर रहे हैं? मैं उनका दोष नहीं निकालता। वे दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते। वे खुद जब अंग्रेजों को मारकर राज्य करेंगे तब आपसे और हमसे (जबरन) कानून मनवाना चाहेंगे। उनके तरीके के लिए यही कहना ठीक है। लेकिन सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसंद नहीं हैं उन्हें वह स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोष के मुँह पर बाँधकर उसकी धज्जियाँ क्यों न उड़ा दी जायँ! आप क्या मानते हैं? तोप चलाकर सैकड़ों को मारने में हिम्मत की जरूरत है या हँसते-हँसते तोप के मुँह पर बँधकर धज्जियाँ उड़ने देने में हिम्मत की जरूरत है? खुद मौत को हथेली में रखकर जो चलता-फिरता है वह रणवीर है, या दूसरों की मौत को अपने हाथ में रखता है वह रणवीर है? यह निश्चित मानिये कि नामर्द आदमी घड़ी भर के लिए भी सत्याग्रही नहीं रह सकता। हाँ, यह सही है कि शरीर से जो दुबला हो वह भी सत्याग्रही हो सकता है। एक आदमी भी (सत्याग्रही) हो सकता है और लाखों लोग भी हो सकते हैं। मर्द भी सत्याग्रही हो सकता है; और भी हो सकती है। उसे अपना लश्कर तैयार करने की जरूरत नहीं रहती। उसे पहलवानों की कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं रहती। उसने अपने मन को काबू में किया कि फिर वह वनराज सिंह की तरह गर्जना कर सकता है; और जो उसके दुश्मन बन बैठे हैं उनके दिल इस गर्जना से फट जाते हैं।

क्रमश: ...

छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दों से लेकर सीएम पद के दावेदारों तक

अभिषेक दीक्षित

छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान होगा। तीन दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक, नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्रों के चलते संवेदनशील माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सात नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा तथा दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा। राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण लिए 13 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होगी। 20 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्तूबर को की जाएगी। 23 अक्तूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 21 अक्तूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी तथा 30 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 31 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दो नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन-कौन से हैं? चुनाव प्रचार में बड़े चेहरे कौन-कौन से हैं? चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं? किन-किन के बीच मुकाबला है? इस बार 2018 के मुकाबले समीकरण कितने अलग हैं? आइए विस्तार से समझते हैं...

इस चुनाव में कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती होगी। वहीं, भाजपा एक बार फिर राज्य की सत्ता में आने की कोशिश करेगी। इस बीच भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। इन सभी 21 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। वहीं, आप ने दो सूची जारी कर राज्य के लिए 22 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस ने अब तक कोई सूची नहीं जारी की है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 71, भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के चार और बसपा का एक विधायक है।

राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और संकेत हैं कि इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही पार्टी चुनाव में जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से कुछ समय पहले टीएस सिंहदेव को पार्टी ने उपमुख्यमंत्री बनाकर कुछ हद तक उनकी नाराजगी दूर करनी की कोशिश की है। पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव के साथ ही साथ ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी भाजपा के रुख की बात करें तो वह इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। स्पष्ट रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें सीएम फेस के रूप में सामने नहीं ला रही है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ-साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रदेश में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के प्रमुख नेता मल्लिकार्जुन खरगे, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी चुनावी कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा है। चेहरा न होने के बावजूद खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनावी कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं। इस चुनाव में मौजूदा सरकार के सामने बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इस साल मार्च में घोषित छत्तीसगढ़ पीएससी की 2021 परीक्षा के परिणाम में भाजपा ने चयन सूची में भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा किया कि नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदारों का चयन किया गया है। वहीं मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी सरकार से जांच करने को कहा है।

राज्य में आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार की जांच ईडी कर रही है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा लगातार राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यस्था के मुद्दों को अपने कार्यक्रमों में उठा रही है। हाल ही में जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है, हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। इस बीच महिला वोटर को साधने के लिए कांग्रेस गारंटियों की बात कर रही है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर कर्नाटक विधानसभा में पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों का जिक्र किया है।

वहीं, भाजपा आगामी चुनाव के लिए महिला आरक्षण को सामने रख रही है। इसके अलावा आप ने छत्तीसगढ़ में भी 10 चुनावी गारंटियां घोषित की हैं। इसमें महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और किसानों से जुड़े मुद्दे रखे गए हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की उम्मीद है। इसके अलावा आप, बसपा जैसे दल भी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं।

2018 में राज्य में दो चरणों मतदान कराए गए थे। पहले चरण का मतदान 12 नवंबर 2018 और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। चुनाव नतीजे आए तो 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 68 और भाजपा को 15 सीटें मिलीं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने पांच सीटें जीते थीं और दो सीटें बसपा के खाते में गई थीं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हुए पांच उपचुनावों में से पांचों पर सत्ताधारी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इनमें से दो सीटें पहले से ही उसके पास थी जबकि पार्टी ने एक सीट भाजपा की तो दो सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की छीन लीं।

जीत की चाह में भाजपा ने किनारे किए अपने ही नियम

समीर चौगांवकर

9 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए तारीखों का ऐलान कर रहा था, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची टाइप हो रही थी। दोपहर को भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए 162 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें राजस्थान की पहली सूची में 41, मध्य प्रदेश की चौथी सूची में 57 और छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची में 64 उम्मीदवारों के नाम हैं। बचे हुए नाम भारतीय जनता पार्टी जल्द जारी कर सकती है। राजस्थान की पहली सूची देखकर लगता है कि टिकट बंटवारे में किसी की नहीं चली, सिर्फ भाजपा हाईकमान की चली है। राजस्थान में 41 सीटों में से 29 पर नए प्रत्याशी उतारकर पार्टी ने साफ कर दिया कि कोई लिहाज नहीं होगा। राजस्थान में ऐसी कुल 19 सीटें हैं, जहां पर तीन बार से पार्टी हार रही है। इसमें 11 सीटों पर पहली सूची में टिकट दिया गया है। इन पर उन प्रत्याशियों को उतारा गया है, जो इस बार कड़ी टक्कर दे सकते हैं। राजस्थान में सांसद नरेन्द्र कुमार को मंडावा से, किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से, राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से और देवजी पटेल को सांचोर से टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे में वसुंधरा राजे को न पूरी तवज्जो दी गई है और न नजरअंदाज किया गया है। कई सीटों पर राजे समर्थकों को टिकट मिले हैं, कुछ जगहों पर टिकट कटे भी हैं। किरोड़ी लाल मीणा, शुभकरण चौधरी, बबलू चौधरी जैसे उम्मीदवार वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। वहीं, उनके बड़े समर्थकों में गिने जाने वाले राजपाल सिंह शेखावत, कालूलाल गुर्जर जैसे नेताओं का टिकट कट गया है। खुद वंसुधरा राजे का नाम पहली सूची में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमण सिंह का नाम घोषित होने के बाद इस बात की संभावना है कि अगली सूची में वसुंधरा का नाम आ सकता है। सात में से तीन सांसदों ने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन राठौर के लिए कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया को झोटवाड़ा से हराना आसान नहीं होगा। तिजारा से बाबा बालकनाथ की जीत आसान है, वहीं सांचौर से देवजी पटेल की परीक्षा होगी। विद्याधर सीट से तीन बार के विधायक और पूर्व मंत्री नरपत राजवी की जगह सांसद दिया कुमारी को टिकट देकर भाजपा ने यह सुनिश्चित किया है कि दिया कुमारी को किसी तरह की चुनौती न मिले। लाल डायरी के कारण चर्चा में आए राजेन्द्र गुढा के लिए भाजपा ने सीट नहीं छोड़ी। भाजपा ने यहां से विधायक रह चुके शुभकरण चौधरी को मौका दिया है। तिजारा से बाबा बालकनाथ को उतारकर भाजपा ने राजस्थान की पहली सूची में हिन्दुत्व का पूरा संदेश देने की कोशिश भी की है। वहीं, 41 सीटों में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका नहीं दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों में से मात्र एक मुस्लिम यूनुस खान को टोंक सीट से उतारा था। सचिन पायलट के कारण 2018 में गुर्जर समाज से झटका खा चुकी भाजपा ने इस बार इस वोट बैंक को फिर से साधने के लिए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवाई कर चुके कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को टिकट देकर चौंका दिया है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने या न लड़ने के बीच भाजपा ने चौथी सूची में शिवराज का नाम घोषित कर संकेत दे दिए हैं कि वह मुख्यमंत्री की दौड़ में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 24 मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं, जबकि अभी चार कैबिनेट और पांच राज्यमंत्री के नाम घोषित नहीं हुए है। सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, बृजेन्द्र सिंह यादव, महेन्द्र सिंह सिसोदिया पर फिलहाल तलवार लटकी है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से बनेगा लोकसभा चुनाव का माहौल!

अवधेश कुमार

चुनाव आयोग ने भले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की औपचारिक घोषणा अब की है, लेकिन देश पहले से ही चुनावी मोड में है। काफी समय से राजनीति की पूरी रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव के इर्द-गिर्द बनाई जा रही है। लोकसभा चुनावों के पूर्व यही विधानसभा चुनाव हैं और इसके परिणाम कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होंगे। कुल 16 करोड़ 14 लाख मतदाताओं, 679 विधानसभा सीटों तथा 83 लोकसभा सीटों का महत्व समझना कठिन नहीं है। इन चुनावों के पूर्व मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के लिए नारी सम्मान वंदन कानून बना दिया है। इन चुनाव में करीब 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता हैं। यह पता चलेगा कि महिलाओं को आरक्षण देने से ये कितना प्रभावित कर सकता है? यह चुनाव भाजपा, कांग्रेस तथा क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के लिए एक हद तक करो या मरो जैसा है। कांग्रेस के लिए इनमें प्रदर्शन से आईएनडीआईए (इंडिया) में राष्ट्रीय राजनीति यानी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उसकी हैसियत तय होगी। यदि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो आईएनडीआईए का नेतृत्व उसके हाथों में आ सकता है। अच्छा नहीं रहा तो आईएनडीआईए में नेतृत्व की दावेदारी तथा सीटों के तालमेल में निचले पायदान पर खड़ी रहेगी। भाजपा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के दो विधानसभा चुनावों में लगातार हार के बाद वह अगली पराजय का जोखिम नहीं ले सकती। यद्यपि 2018 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान विधानसभा चुनावों में पराजय के बावजूद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन राज्यों में बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की थी। लेकिन, लगातार पराजय से पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा होगी तथा विपक्ष लाभ उठा सकता है। प्रश्न है कि क्या इन चुनाव में पार्टियां अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम लाने में सफल होंगी? चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी हमेशा जोखिम भरी होती है इसलिए इससे बचना चाहिए।यह सच है कि इस समय भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में अपनी राज्य सरकारों और वहां के नेतृत्व के विरुद्ध असंतोष और गुस्सा है क्योंकि शासन में उनकी व्यापक अनदेखी हुई है। जनता के अंदर किसी राज्य में भाजपा के विरुद्ध व्यापक गुस्स नहीं है, किंतु कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे या विरोध में चले जाएंगे तो विजय मुश्किल होती है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक इसका उदाहरण है। इस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के पास विजय का अवसर है। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, उनके प्रति कार्यकर्ताओं-समर्थकों का विश्वास भी है।

अजब एमपी की गजब पॉलिटिक्स

सिद्धार्थ शंकर गौतम

कुछ साल पहले एमपी टूरिज्म का एक विज्ञापन आया था जिसमें बताया जाता था कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस समय मध्य प्रदेश की राजनीतिक दशा बिल्कुल उस टूरिज्म डिपार्टमेन्ट के विज्ञापन जैसी हो गयी है। दो दलीय राजनीति के सिरमौर मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में अजब गजब वाली स्थिति ही उत्पन्न हो गई है। एक ओर जहां भाजपा दूल्हे का नाम लिये बिना बारात सजाने में लगी है वही कांग्रेस में चुनावी दूल्हा तो तय है लेकिन बारातियों का फैसला नहीं हो पा रहा है। भाजपा ने जहां आचार संहिता घोषित होते ही 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है वहीं कांग्रेस अब तक नामों पर ही आम सहमति बनाने के प्रयास में है। हां, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है और निर्विवाद रूप से अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं जबकि भाजपा ने कार्यकर्ता आधारित चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय बढ़ा दिया है। तीन केंद्रियों मंत्रियों सहित 4 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव के अलावा मुख्यमंत्री पद के कथित दावेदार 4 से 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट देकर भाजपा नेतृत्व ने मैदान खुला रखा है। यदि पुन: भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे अधिक राजनीति मुख्यमंत्री पद को लेकर होना तय है। राजनीति तो खैर अभी भी हो रही है क्योंकि जैसे-जैसे भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, टिकट के संभावित उम्मीदवार बग़ावत पर उतर आए हैं। कटनी से भाजपा की अधिकृत पूर्व महापौर प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित ने चौथी सूची आते ही अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा को अलविदा कह दिया है। ज्योति विनय दीक्षित को विजयराघोगढ़ के विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक का करीबी माना जाता है। बग़ावत के समाचार अन्य स्थानों से भी हैं जो भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है।

भाजपा संगठन इस बग़ावत की धार को कैसे कुंद करता है यह देखना दिलचस्प होगा किंतु एक बात तो तय है कि अब जबकि मध्य प्रदेश में मतदान के मात्र 37 दिन शेष हैं, भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार और जनता के बीच जाने का समय दिया है जबकि कांग्रेस की ओर से टिकट की आस लगाए प्रत्याशी हाईकमान का मुंह ताकने को विवश हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि अभी पितृ पक्ष में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची होल्ड पर ही रहेगी। अर्थात नवरात्रि में सूची आने के बाद अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशियों के पास चुनाव प्रचार हेतु एक माह से भी कम समय रहेगा। अब इस एक माह में वह पहले अपनी ही पार्टी में गुटबाजी को रोकेगा, संभावित भीतरघात से बचने के लिए डैमेज कंट्रोल करेगा और फिर जनता के बीच जाकर वोट मांगेगा। यह स्थिति ठीक ऐसी ही है मानो व्यक्ति ने स्वयं को राजा तो घोषित करवा दिया किंतु उसके मंत्रिमंडल में कौन होगा इसका अभी उसे ही पता नहीं है।

प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को लेकर भी कांग्रेस की उहापोह सार्वजनिक हो गई है। संघ के गढ़ शाजापुर जिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आमसभा में दिग्विजय सिंह दूसरी पंक्ति में खड़े नजर आए मानो उनका चेहरा पार्टी आगे करना ही नहीं चाहती हो। दरअसल, भाजपा नेतृत्व चाहता है कि दिग्विजय सिंह की चुनावी सक्रियता जनता को दिखे ताकि उनकी कार्यशैली, उनका विकासहीन कार्यकाल और उनके हिंदू विरोधी बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस को बैकफुट पर लाया जा सके। कांग्रेस भी भाजपा की मंशा को समझती है अत: उसने दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे ही रखा है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के समर्थकों को लेकर भी कांग्रेस सतर्क है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस में मुख्यत: दो ही क्षत्रप शेष हैं। एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। शेष सुरेश पचौरी, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया जैसे पुराने क्षत्रपों ने इनकी शरण में आना उचित समझा है जिससे इनके समर्थक भी अब राजाजी और कमलनाथ में बंट गए हैं। जैसे दूध का जला छांछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, वैसे ही कांग्रेस आलाकमान दिग्विजय सिंह को लेकर अति सावधान है। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जितने नेता बागी बनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, उनमें 60 प्रतिशत से अधिक दिग्विजय सिंह के कोटे से थे और कांग्रेस 2008 के मुकाबले 13 सीटें गंवाकर मात्र 58 सीटों पर सिमट गई थी। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं बनी किन्तु अब पुन: दिग्विजय सिंह के खास समर्थक टिकट मांग रहे हैं और यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो कईयों ने निर्दलीय मैदान में उतरने का मन बना लिया है। कांग्रेस की यही उहापोह संभवत: प्रत्याशियों की सूची को सार्वजनिक करने से रोक रही है और मैराथन बैठकें कर आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2018 में मुख्यमंत्री बने कमलनाथ यदि 5 वर्षों तक सत्ता चला लेते तो जनता के समक्ष उनके कार्यकाल की समीक्षा का अवसर भी होता किन्तु मात्र डेढ़ वर्ष में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से उन्हें अपदस्त कर शिवराज सिंह चौहान पुन: मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस और कमलनाथ को लगता है कि यही एक कारण उन्हें जनता के बीच भावनात्मक जीत दिलवा देगा जबकि ऐसा नहीं है। एक ओर जहां भाजपा बीते तीन माह से चुनावी मोड में है और केंद्रीय मंत्रियों की फौज प्रदेश में उतर चुकी है, वहीं कांग्रेस न तो सड़क पर दिख रही है और न ही जनता के बीच। इतने पर भी कमलनाथ का अति-आत्मविश्वास कहीं न कहीं यह दर्शा रहा है कि वे इस मुगालते में हैं कि जनता उनकी मुख्यमंत्री पद से विदाई का बदला भाजपा को हरा कर लेगी जबकि ऐसा नहीं है। भाजपा के समक्ष असल चुनौती कांग्रेस नहीं बल्कि पार्टी के भीतर घर कर गई कांग्रेसी संस्कृति है जिसके चलते गुटबाजी, भितरघात, पार्टी संगठन की अनदेखी, क्षेत्रों में क्षत्रप राजनीति करना आदि भाजपा में आ गई हैं। फिर इतने वर्षों की एंटी-इन्कंबेंसी भी भाजपा के विरोध में जा सकती है अन्यथा तो मध्य प्रदेश में अभी तक भाजपा के पक्ष में ही माहौल है बशर्ते चेहरे को लेकर स्थिति साफ हो जाए। चंबल, महाकोशल और विंध्य क्षेत्र में जहां कांग्रेस मजबूत दिख रही है वहीं मालवा, निमाड़, मध्य भारत और बुंदेलखंड में भाजपा का दम दिखाई देता है। अब सारा फोकस इस बात पर है कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन हो?

उत्तरप्रदेश में दलित वोट पर सभी दलों का दांव

अनिल तिवारी

इस बार बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस (9 अक्टूबर) पर अकेले बसपा ने कार्यक्रम नहीं किये। कांग्रेस और सपा की ओर से भी धूमधाम से मान्यवर कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कांग्रेस की ओर इसी दिन राज्यव्यापी दलित गौरव संवाद यात्रा की शुरुआत हुई है जो 26 नवंबर संविधान दिवस तक चलेगी। यूपी में दो विधायक और एक सांसद तक सिमट चुकी कांग्रेस को उम्मीद है कि कांशीराम की बसपा के उभार के साथ जो दलित वोटर उससे छिटक गये थे अब मान्यवर कांशीराम का नाम लेने से वापस आ जाएंगे। असल में पिछले महीने उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में बसपा नेत्री मायावती ने अपने मतदाताओं से अपील की थी कि दलित समाज के लोग या तो वोट न करें या फिर नोटा का बटन दबाकर अपना वोट डाल दें। बीएसपी मुखिया की यह अपील उनके ही अधिकांश समर्थकों ने ठुकरा दी। बहुजन समाज पार्टी के लिए तो यह खतरे की घंटी साबित हुई, लेकिन यहीं से सपा, कांग्रेस और भाजपा के लिए उम्मीदों का एक नया दरवाजा भी खुल गया है। यह दरवाजा है मायावती के दलित वोट बैंक में पैठ बनाने का।

सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। यही कारण है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 80 सीटों के लिए दलित वोटरों को अपना बनाने के लिए सबने अपनी-अपनी न सिर्फ रणनीति तैयार कर ली है बल्कि बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है। मजेदार बात यह है कि सभी दलों ने दलित वोट हासिल करने के लिए घुमा फिरा कर उसी तरह की योजना तैयार की है जिसे दशकों पहले कांशीराम ने सबसे पहले आजमाया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर दलित समाज को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की अपील की है। लखनऊ में आयोजित पार्टी की अंबेडकर वाहिनी की बैठक को संबोधित करते हुए दलित समाज को जोड़ने का अभियान तेज करने का आह्वान किया। पिछले दो चुनावों में मिली हार से समाजवादी पार्टी लगभग किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में है। इस दरमियान येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह-तरह के सुलह समझौते भी करती रही है। जिस कांग्रेस का विरोध कर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उनके रहते ही गद्दी पाने की लालसा में अखिलेश यादव ने उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां कर पार्टी की मिट्टी पलीत कर दी।

हालांकि इस गठजोड़ का लाभ उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों का आंकड़ा कुछ बढ़ा लिया था, लेकिन सपा के हाथ निराशा ही आई थी। इसी तरह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद अखिलेश यादव ने बसपा के साथ भी चुनावी गठबंधन किया था। चुनाव में मशहूर बुआ-बबुआ की जोड़ी का भी कमोबेश वही हश्र हुआ, जैसा सपा-कांग्रेस का पिछले चुनाव में हुआ था। बरसों बाद दलित वोटो की संजीवनी से समाजवादी पार्टी को घोसी उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत मिली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित मतदाताओं से वोट न करने अथवा नोटा का बटन दबाने की अपील की थी, लेकिन उनके आदेश को अनसुना कर दलितों ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा समाजवादी पार्टी या भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया। पार्टी के पक्ष में परिणाम आने के बाद से ही सपा प्रमुख पार्टी की अंबेडकर वाहिनी को सक्रिय करने में जुट गए। मिले मुलायम काशीराम.. के फार्मूले को नए सिरे से परिभाषित करते हुए दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया।

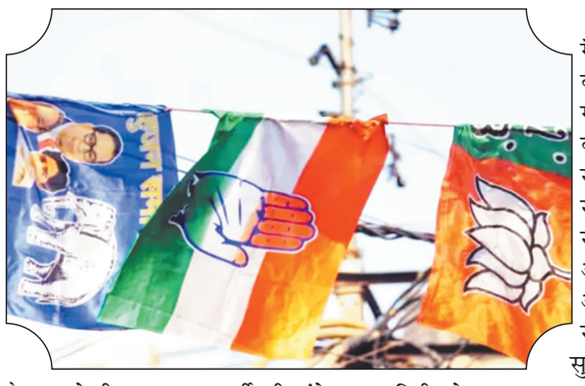

असल में दलित समाज के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली बसपा पिछले एक दशक से लगातार कमजोर हो रही है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में आज उसके पास केवल एक सीट है, जिसके कारण बहुजन आंदोलन भी कमजोर होता जा रहा है। प्रदेश के करीब 22त्न दलित वोटो पर बीएसपी का कब्जा था लेकिन अब माना जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जमीनी राजनीति से सक्रियता खत्म होने के कारण दलित वोटो में भी बिखराव हो रहा है।

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.24 प्रतिशत वोट पाने वाली मायावती की पार्टी का वोट शेयर विधानसभा चुनाव 2022 में 12.81त्न रह गया है। माना जा रहा है कि बीएसपी के पास दलितों में केवल हरिजन/जाटव वोट बचा है, गैर हरिजन/जाटव वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ गया है अथवा सपा के पास चला गया है। वर्तमान में कांग्रेस के पास विधानसभा की दो सीटें हैं जबकि संसद में केवल एक सीट है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी भाजपा की। भाजपा के सभी सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी और बाकी जिम्मेदार नेता दलित जोड़ो अभियान पर मंथन कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति के दो फार्मूले हैं, लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों के लिए अलग तैयारी और बाकी 63 सीटों के लिए दूसरी तरह की योजना है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दलित समाज को जोड़ने की योजना बनाई गई है।

दलितों को अपना बनाने के लिए अगले लोकसभा चुनाव तक की पूरी योजना बीजेपी ने तैयार कर ली है। तय हुआ है कि यूपी के कुछ शहरों में ऐसी रैली की जाए जिससे देश भर में संदेश जाए। प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में दलित महासम्मेलन किया जाएगा जिसमें पार्टी के बड़े नेता हिस्सा लेंगे। आगे चलकर जिलों में भी पार्टी दलित सम्मेलन और रैली करने की योजना तैयार की है। बस्ती संपर्क अभियान के तहत बस्तियों में लाभार्थियों से संपर्क सहित समाज के प्रबुद्ध वर्ग, सेवानिवृत अधिकारी, खिलाड़ी, लोक कलाकारों व अन्य प्रमुख लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने की भी पार्टी ने योजना तैयार की है। राजनीति में दलित दखल की बात करें तो भारतीय राजनीति में एक नारा बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया गया जो काफी चर्चित हुआ था। जगजीवन राम की आई आंधी, उड़ जाएगी इंदिरा गांधी नारा लगा भी खूब और जनता पार्टी की सरकार भी बनी। लेकिन जगजीवन राम पीएम नहीं बन सके। जनता पार्टी में पीएम पद के तीन दावेदार थे, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम।

जब मोरारजी देसाई पीएम बन गए तो दलित समुदाय में काफी रोष आ गया, कहा जाता है कि उस समय देश में कई दलित घरों में खाना नहीं बना था। दलितों में पनपे इस रोष को आगे बढ़ाया काशीराम ने। उन्होंने भी शुरूआत दलित चेतना के आंदोलन से की। उन्होंने दलित के साथ पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा। सरकारी दफ्तरों में इन वर्गों के संगठन बनाए। इसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। अंबेडकर की विचारधारा को जमीन पर उतरने का काम कांशीराम ने किया और उसे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने का काम मायावती ने। देश में दलितों की संख्या 22 प्रतिशत है। इनमें भी सबसे ज्यादा 55 प्रतिशत के करीब जाटव/हरिजन हैं और 45 प्रतिशत गैर जाटव हैं। दलितों की कुल 66 उपजातियां हैं, इनमें से 55 का संख्या बल ज्यादा नहीं है। कुछ जिले दलितों के प्रभाव वाले हैं। जाटव का प्रभाव आगरा, आजमगढ़, जौनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर में देखने को मिलता है, वहीं सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, प्रयागराज और लखनऊ में पासी, तथा बरेली, सुल्तानपुर, गाजियाबाद में कोरी धोबी जातियों की संख्या ज्यादा है। भाजपा के हिन्दुत्ववादी विस्तार के बाद से ही दलित के नाम पर होने वाली राजनीति कमजोर पड़ी है और नेतृत्व भी नेपथ्य में दिख रहा है। यह अलग बात है कि दलितों की अहमियत राजनीति में कम नहीं हो रही, और सभी दल दलित मतदाताओं को लुभाने की होड़ में लगे हैं।

सूची देर से जारी करने के पीछे रणनीति तो नहीं?

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित दो अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एमपी, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की अगली सूची कुछ दिनों में आने की उम्मीद है। इधर, कांग्रेस ने अभी तक चुनावी राज्यों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। छत्तीसगढ़ में सात नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होना है, समय कम है, फिर भी कांग्रेस शुभ मुर्हूत का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि नवरात्र के पहले दिन सूची जारी की जा सकती है। अभी पितृ पक्ष चल रहा है। ऐसे में कोई लिस्ट जारी करना शुभ नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सूची जारी करने के पीछे हो सकता है कि कांग्रेस की कोई रणनीति हो। अगर पार्टी नवरात्र में उम्मीदवार घोषित करती है तो यह पार्टी का हिंदुत्व कार्ड साबित होगा। पार्टी इस बहाने से यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि वह शास्त्रों और नक्षत्रों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं पर भी विश्वास करती है। नवरात्र से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। यह दांव भाजपा पर भारी पड़ सकता है। शास्त्रों में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृों को समर्पित किया गया है। यहीं वजह है कि इन 15 दिनों में देवकार्य नहीं किए जाते है। लेकिन

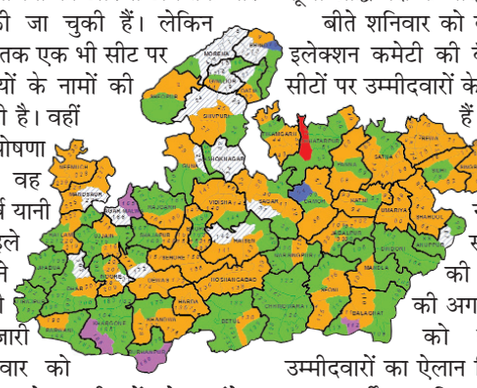

एमपी में भाजपा की ओर से अब तक चार सूची जारी की जा चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक वह नवरात्रि की पर्व यानी नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। मंगलवार को सतना में मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके है कि कांग्रेस की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी।

बीते शनिवार को कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में लगभग 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। लेकिन पितृ पक्ष के चलते नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 13 अक्टूबर को होगी। इसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 136 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।

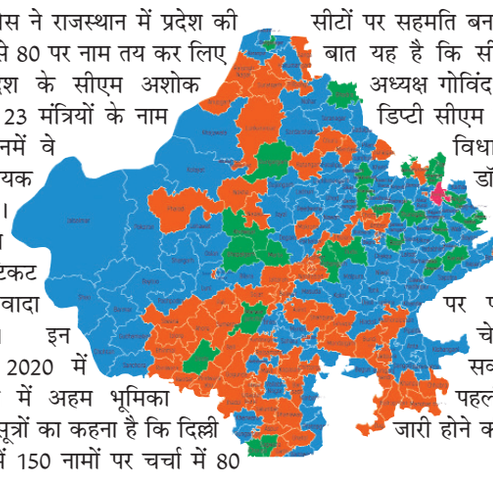

इधर, कांग्रेस ने राजस्थान में प्रदेश की 200 सीटों में से 80 पर नाम तय कर लिए है। इसमें प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत समेत 23 मंत्रियों के नाम शामिल है। इनमें वे निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। जिन्हें गहलोत ने कांग्रेस से टिकट दिलाने का वादा किया था। इन विधायकों ने 2020 में सरकार बचाने में अहम भूमिका अदा की थी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में हुई बैठक में 150 नामों पर चर्चा में 80 सीटों पर सहमति बन गई है। इसमें खास बात यह है कि सीएम गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीपी जोशी के खेमे सहित सर्वे में शामिल नाम है। बाकी 120 सीटों पर पार्टी महिला, युवा चेहरे को मौका दे सकती है। 50 नामों की पहली सूची नवरात्र में जारी होने की उम्मीद है।

● राहुल संपाल

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए 13 अक्तूबर को केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठक पहले हो चुकी हैं। 90 में से 65 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं। 25 सीटों पर पैनल में दो या तीन नाम पर अभी निर्णय होना बाकी है। इसके अलावा वर्तमान के 17 विधायकों की खराब परफॉर्मेंस के कारण पार्टी टिकट कट सकती है।

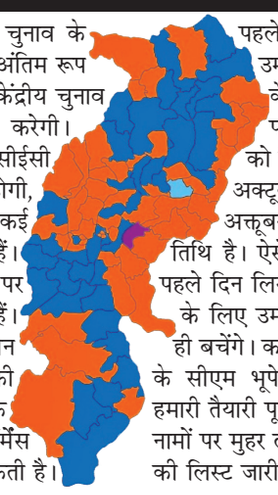

पहले चरण के सभी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्रि के पहले ही हो जाएगी। क्योंकि पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को है। इसके लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर से ही शुरु हो जाएगी। 20 अक्तूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। ऐसे में अगर कांग्रेस नवरात्र के पहले दिन लिस्ट जारी करती है तो नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास महज 5 दिन ही बचेंगे। कांग्रेस की सूची को लेकर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि, हमारी तैयारी पूरी हैं। अगली बैठक सीईसी से नामों पर मुहर लग जाएगी। नवरात्रि में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी।

पिछले दो चुनाव में सिर्फ 8 महिलाओं ने बेमेतरा से ठोकी दावेदारी

लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन के दोनों सदनों में महिला आरक्षण को सर्वसम्मित से पारित कर दिया गया है. यह आरक्षण राजनीति और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लाया गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में हुए पिछले दो विधानसभा चुनाव के दौरान बेमेतरा जिले में 80 पुरुषों की तुलना में महज 4 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया था.

कब कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतरे?- वर्ष 2013 के चुनाव में साजा विधानसभा में 9 उम्मीदवार थे. बेमेतरा में 18 प्रत्याशी में से एक महिला प्रत्याशी थीं. नवागढ विधानसभा में 9 दावेदार थे, जिनमें दो महिला प्रत्याशी थीं. 218 में साजा विधानसभा में 16 दावेदार चुनाव मैदान में थे, जिनमें केवल एक महिला प्रत्याशी दावेदारी कर रही थी. बेमेतरा और नवागढ़ से 16-16 दावेदार मैदान में थे, जिसमें एक भी महिला शामिल नहीं थीं.

बेमेतरा जिले की तीन सीटों पर महिलाओं को अवसर कम मिले - बेमेतरा जिले की तीन विधानसभा सीटों में प्रत्याशी के रूप में महिलाओं को कम ही मौका मिला है. पिछले दो चुनावों की बात करें तो केवल चार महिलाओं ने विधान सभा चुनाव में भाग्य आजमाया है. इनमें से केवल एक महिला को ही राष्ट्रीय पार्टी से दावेदारी करने का अवसर मिला. वर्ष 213 में नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस ने अनिता पात्रे को उम्मीदवार बनाया था. हालांकि परिणाम आने पर 19 हजार 19 मत पाकर वे तीसरे स्थान पर रहीं. एक अन्य महिला दावेदार कांति बाई को 2 हजार 438 वोट मिले थे. इसी दौरान बेमेतरा विधानसभा सीट से बीएचबीपी की दावेदार के तौर पर प्रभादेवी पटेल चुनाव लड़ी थीं. 2018 के चुनाव में साजा से कौशल्या नारंग चुनावी मैदान में उतरी थीं.

हजारों महिला मतदाता, फिर क्यों नहीं होती दावेदारी?- मतदाता सर्वेक्षण के माध्यम से मतदाताओं की संख्या भी सामने आ चुकी है. साजा विधानसभा में 87 हजार 176 पुरुष व 81 हजार 677 महिला मतदाता समेत एक लाख 63 हजार 855 मतदाता हैं. बेमेतरा विधानसभा में एक लाख 14 हजार 96 पुरुष व 11 हजार 4470 महिला मतदाता समेत 2 लाख 28 हजार 568 वोटर्स हैं. वहीं नवागढ़ विधानसभा में 2 लाख 66 हजार 172 मतदाता हैं, जिसमें से एक लाख 34 हजार 871 पुरुष और एक लाख 31 हजार 299 महिला मतदाता इस बार मतदान करेंगी. वोटर लिस्ट में महिला मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या दिख रही है लेकिन जन प्रतिनिधि बनने के लिए महिलाएं यहां से क्यों नहीं सामने आतीं ये बड़ा सवाल है.

छत्तीसगढ़ के इन दो संभागों से खुलती है सत्ता की चाबी, यही से सजता है मुख्यमंत्री का ताज

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 7 नवंबर को पहला चरण और 17 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसे में प्रदेश के दो महत्वपूर्ण संभागों यानी सरगुजा और बस्तर में पूरे प्रदेश की निगाहें रहेगी। क्योंकि सरगुजा और बस्तर संभाग से छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी खुलती है। इन्हीं दो संभागों से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता तय होता है। यही से मुख्यमंत्री का ताज सजता है।

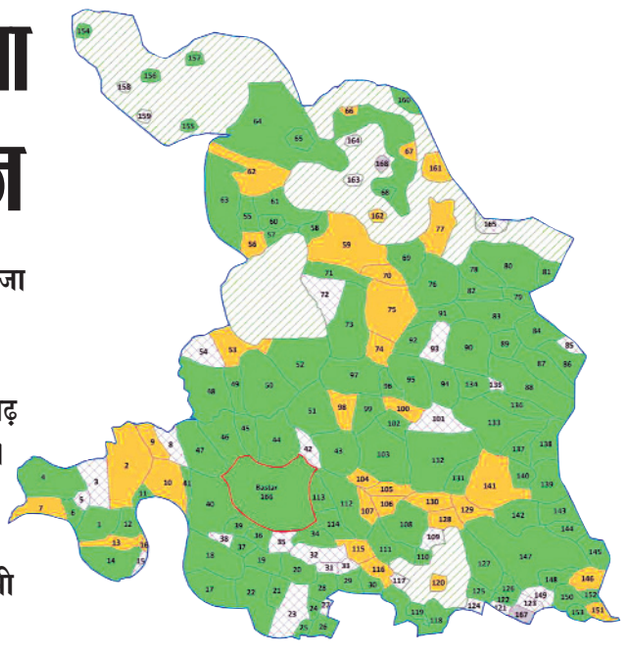

इसलिए माना जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, तो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के किलों पर फतह हासिल करना बहुत जरूरी है। इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। इस बार के चुनाव में जहां कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती रहेगी। वहीं बीजेपी एक बार फिर राज्य की सत्ता में आने की पूरजोर कोशिश करेगी। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए 85 उम्मीदवारों का एलान कर चुकी है। केवल 5 सीटों की घोषणा होनी बाकी है।

छत्तीसगढ़ में बसपा ने 8 अगस्त को 9 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और 10 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट में 17 प्रत्याशियों को मौका दिया है।

इस तरह कुल 26 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। इसके बाद बीजेपी ने 17 अगस्त को 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। फिर 9 अक्टूबर को 64 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इस तरह कुल 85 प्रत्याशियों को टिकट दे चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची 8 सितंबर और दूसरी 2 अक्टूबर को जारी की थी। पहली सूची में जहां 10 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। वहीं दूसरी सूची में 12 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह से आप ने अब तक कुल 22 प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतार चुकी है। वहीं राज्य में सत्ता पर आसीन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है।

ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 71, भाजपा के 13, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के 3 और बसपा के 2 विधायक हैं। एक सीट खाली है।

6 जिलों वालें सरगुजा संभाग में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। संभाग के 6 जिलों में सरगुजा, कोरिया, रामानुजगंज- बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर शामिल हैं। इन जिलों की अधिकांश आबादी आदिवासी है। इन्हीं आदिवासी वोटर्स को कांग्रेस और बीजेपी दोनों साधने की कोशिश में लगी हैं। दोनों ही आदिवासी हितैषी होने का दावा करते हुए वोट मांग रही हैं।

बात वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की करें, सरगुजा संभाग की 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यहीं से काग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी खुलती है। कांग्रेस को सुरगजु के बाद बस्तर से बड़ी जीत मिली थी। और 15 साल का कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ था। 2018 में सरगुजा में बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। टीएस सिंहदेव की वजह से निर्णायक जीत मिली थी क्योंकि वहीं घोषण पत्र तैयार किए थे। संभाग की जनता उन्हें सीएम मानकर चल रही थी क्योंकि साल 2018 में प्रदेश में सीएम का कोई चेहार घोषित नहीं था। संभाग में बाबा का वर्चस्व हार जीत तय करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में सरगुजा संभाग की 14 सीटें काफी अहम है। यहां की 14 में से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनावों में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 7 सीटों पर कांग्रेस आसीन थी। यानी 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहां काफी नुकसान उठाना पड़ा।

जानें 14 सीटों का समीकरण

सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल्य जिला है, यहां के 6 जिलों में 14 विधानसभा सीट हैं, इन 14 सीटों में 9 सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और महज 5 सीट सामान्य वर्ग के लिए हैं। इन सभी 14 सीट में पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जिनमें से तीन विधायक को भूपेश कैबिनेट में जगह मिली थी। जिसमें दो आरक्षित वर्ग की सीट से विधायक बने थे और एक सामान्य सीट से कैबिनेट मंत्री बने थे। फिलहाल आरक्षित वर्ग से अमरजीत भगत ही कैबिनेट मंत्री हैं। कुछ दिन पहले डॉ प्रेमसाय सिंह को पार्टी हाईकमान के आदेश पर इस्तीफा दे दिए थे। सरगुजा संभाग की 14 सीटें छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी खोलती हैं। जिसकों यहां से बढ़त मिली समझो उसकी सरकार यहां बनना तय माना जाता है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा को जिन 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उनमें 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। ये सीटें भरतपुर सोनहत, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, प्रतापपुर हैं। 2 सामान्य सीटें मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था।

सरगुजा संभाग में 6 जिले

सरगुजाद्व कोरिया, रामानुजगंज-बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें

अंबिकापुर, लुंड्रा, प्रतापपुर, सीतापुर, सामरी, रामानुजगंज, प्रेम नगर, भटगांव, बैकुंठपुर, भरतपुर-सोनहत, मनेंद्रगढ़, जशपुर , कुनकुरी, पत्थलगांव

बीजेपी-कांग्रेस को अब तक मिली सीटें

वर्ष	भाजपा	कांग्रेस
2003	10	04
2008	09	05
2013	07	07
2018	0	14

बस्तर संभाग के सियासी गणित की करें तो आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं। 7 जिलों के संभाग में यहां छत्तीसगढ़ की 12 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में 11 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) और एक सीट सामान्य है। इनमें बस्तर, कांकेर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर की सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं जगदलपुर विधानसभा सीट सामान्य है। 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहीं से करारी हार का सामना करना पड़ा था और सत्ता गंवानी पड़ी थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से बस्तर संभाग काफी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर से खुलती है। इसलिए माना जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, तो बस्तर किला पर फतह हासिल करना बहुत जरूरी है। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 29 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं और 29 में से 12 सीटें बस्तर संभाग से आती हैं। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को साल 2018 में यही से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसलिए बीजेपी में सत्ता पाने की बैचेनी है। बस्तर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओपी माथुर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता दौरा कर चुके हैं और कर रहे हैं। बस्तर में पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बस्तर का चुनावी दौरा कर चुके हैं।

बस्तर संभाग में 7 जिले

बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव

बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें

बस्तर, जगदलपुर, कांकेर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर

11 सीटें एसटी के लिए आरक्षित

केवल 1 सीट जगदलपुर सामान्य

वर्तमान में 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा

प्रदेश में 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित, इनमें 12 सीटें बस्तर संभाग से हैं

बीजेपी-कांग्रेस को अब तक मिली सीटें

वर्ष	भाजपा	कांग्रेस
2018	00	12
2013	04	08
2008	11	01
2003	08	04

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. बीजेपी,कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रही हैं, लेकिन आज हम आपको उस विधानसभा सीट का समीकरण बताएंगे, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे 90 सीटों में सबसे कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था.

2018 में धमतरी सीट पर सबसे कम मार्जिन से हुआ था हार-जीत का फैसला

दरअसल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 77 किलोमीटर दूर धमतरी जिले की धमतरी विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की राजनीति और इतिहास में अहम रही है. 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था. बीजेपी ने सत्ता गंवाई और 15 सीटों पर अटक गई. इसी में से एक धमतरी सीट पर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन हार जीत का फैसला बेहद कम मार्जिन 464 वोट से हुआ. बीजेपी को 36.64 और कांग्रेस को 36.37 फीसदी वोट मिले. इसलिए 2018 में धमतरी विधानसभा सीट में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी.

2018 विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या था

धमतरी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 9 हजार 652 है. इसमें से 1 लाख 72 हजार 482 मतदाताओं ने मतदान किया, जोकि 82.27 फीसदी है. बीजेपी प्रत्याशी रंजना दीपेंद्र साहू को 63 हजार 198 वोट मिले, यानी 36.64 फीसदी वोट शेयर. वहीं कांग्रेस के गुरमुख सिंह होरा को 62 हजार 734 वोट मिले. यानी 36.37 फीसदी वोट शेयर. बीजेपी और कांग्रेस के बीच हार जीत का मार्जिन केवल 464 वोट का रहा. दरअसल, इस हार जीत के मर्जिन को निर्दलीय प्रत्याशी आनंद पवार ने घटाया. पवार को 29 हजार 163 वोट मिले. यानी उनका वोट शेयर 16.91 रहा. इन आंकड़ों को देखने समझने पर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमतरी विधानसभा सीट इस बार काफी दिलचस्प रहने वाली है.

पांच चुनावों कांग्रेस तीन बार जीती

धमतरी विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में रहा है. 1998 से 2018 तक हुए पांच विधानसभा चुनावों में से तीन बार यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की और दो बार बीजेपी ने जीत दर्ज की. इस दौरान कांग्रेस की तरफ से गुरमुख सिंह होरा दो बार विधायक रहे. वहीं बीजेपी यहां से लगातार अपने प्रत्याशी बदलती रही है. 1998 के अविभाजित छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस की जीत हुई थी. वहीं राज्य गठन के बाद पहले विधानसभा चुनाव 2003 में बीजेपी ने धमतरी विधानसभा पर कब्जा जमाया.

ओबीसी वोट बैंक का दबदबा

इसके बाद लगातार गुरमुख सिंह होरा ने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में गुरमुख सिंह होरा केवल 464 वोट से हार गए. धमतरी विधानसभा में ओबीसी वोट बैंक का दबदबा है. खासकर साहू वोटर धमतरी में हार जीत का फैसला करते हैं, लेकिन पिछले पांच साल में विकास के लिए धमतरी तरसता रहा है. इसलिए विकास का मुद्दा इस क्षेत्र में बड़ा है. क्योंकि धमतरी खेती किसानी पर निर्भर रहने वाला विधानसभा क्षेत्र है. वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो धमतरी का इतिहास इसको नकारता है. क्योंकि गुरमुख सिंह होरा इस क्षेत्र में दो बार विधायक रह चुके हैं.

धमतरी विधानसभा का इतिहास

बीजेपी ने इससे पहले भी साहू प्रत्याशी को मैदान में उतरा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी. वहीं 2018 में बीजेपी की प्रत्याशी रंजना दीपेंद्र साहू को जीत मिली थी. धमतरी विधानसभा का इतिहास आजादी की लड़ाई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है. क्योंकि 1920 में इसी क्षेत्र के कंडेल गांव में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ कंडेल सत्याग्रह किया था. इसमें शामिल होने के लिए महात्मा गांधी ने रायपुर से कंडेल तक पदयात्रा की थी. तब अंग्रेजों ने किसानों पर लगाए पानी चोरी का आरोप वापस लिया था. उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी. इसलिए धमतरी क्षेत्र को स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ कहा जाता है.

इसी इलाके से छत्तीसगढ़ के बड़े-बड़े नेताओं की राजनीति में सक्रियता रही है. इसमें बाबू छोटे लाला श्रीवास्तव और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का देश में प्रतिनिधित्व किया. सुंदरलाल शर्मा ने ही महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आयोजन किया था. महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बताया. इसके बाद शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाने लगा.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

संजय सिंह 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को शुक्रवार को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अदालत में पेश किया। ईडी की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सिंह को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया। एजेंसी ने राज्यसभा सदस्य सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कैलाश विजयवर्गीय का राहुल और प्रियंका पर बड़ा वार

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां कर रही है। राजनीतिक दलों का एक-दूसरे पर प्रहार भी जारी है। इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के साथ-साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो झूठ के अलावा वे कुछ भी नहीं हैं। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि गुरुवार को उन्होंने वन अधिकार के पट्टों को लेकर बोला, वन अधिकार के पट्टे सर्वाधिक भाजपा सरकार ने दिए। वनों में आदिवासियों के अधिकार को भाजपा ने सुरक्षित किया है। कांग्रेस जबरदस्ती झूठ बोलकर भाजपा पर आरोप लगा रही है। दरअसल, प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित किया था।

विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यदि स्पीकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने में विफल रहते है तो वह एक समयसीमा तय करेगा। पीठ ने कहा कि हम इस अदालत की गरिमा बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। हमारे आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। उसने कहा कि स्पीकर को अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना होगा अन्यथा पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगी। पीठ ने कहा कि अगर वह स्पीकर की समयसीमा से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्देश देगी कि दो महीने के भीतर फैसला लिया जाये। पीठ ने कहा, जब भारत के संविधान के विपरीत कोई फैसला आता है तो इस अदालत की आज्ञा चलनी चाहिए।

विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष करें फैसला

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की। इसके अलावा, पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियों को लेकर हमला बोला। शरद पवार ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी और शिवसेना (यूबीटी) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को समयबद्ध तरीके से कुछ विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि मामले में देरी की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है।

चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

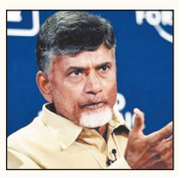

अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू 307 मामले में अग्रिम जमानत दे दी। हालाँकि, टीडीपी प्रमुख जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दो अन्य मामले - इनर रिंग रोड और फाइबर नेट मामला लंबित हैं। अंगल्लू मामला अगस्त में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के स्थानीय नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के चंद्रबाबू नायडू और कई अन्य टीडीपी नेताओं के खिलाफ आरोपों से संबंधित है। वाईएससीआरसीपी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले में एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नायडू और अन्य टीडीपी नेताओं ने अगस्त में अंगल्लू गांव में एक राजनीतिक रैली के दौरान वाईएसआरसीपी नेताओं पर हमला किया।

पी20 की बैठक में बोले प्रधानमंत्री, युद्ध से किसी का भला नहीं

आतंकवाद से त्रस्त दुनिया, एक समान परिभाषा पर अब भी सहमति नहीं: मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले को याद किया और कहा कि दुनिया आतंकवाद से प्रभावित थी, लेकिन फिर भी एक समान परिभाषा पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा, आतंकवाद की परिभाषा पर सहमति न बन पाना दुखद है, मानवता के दुश्मन इसी दृष्टिकोण का फायदा उठा रहे हैं। दुनिया भर की संसदों को इस बारे में सोचना होगा कि हमें आतंकवाद से निपटने के लिए कैसे मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली में नौवें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आतंकवादी जानते थे कि हमारी संसद चल रही है और वे इसे खत्म करना चाहते थे।

प्रधानमंत्री ने साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा, यह समय सबके विकास का है। भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है और आतंकवादियों ने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की है। दुनिया अब समझ रही है कि आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती है और यह मानवता के खिलाफ है। चल रहे इजराइल-हमास युद्ध के स्पष्ट संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी, आज दुनिया जिन संघर्षों और टकरावों का सामना कर रही है, उससे किसी को फायदा नहीं होता है। एक विभाजित दुनिया मानवता के सामने चुनौतियों का समाधान नहीं दे सकती है। हमें वैश्विक विश्वास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से देखना होगा। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जन-भागीदारी ही सर्वोत्तम माध्यम है। कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने संसदीय प्रथाओं का भी जिक्र किया और कहा, यह दुनिया भर की विभिन्न संसदीय प्रथाओं का एक अनूठा संगम है। देश की संसदीय प्रथाएं विकसित और मजबूत

हुई हैं। पीएम ने कहा, जी20 की अध्यक्षता ने भारत में पूरे साल उत्सव सुनिश्चित किया, चंद्रमा पर भारत के उतरने से उत्सव में चार चांद लग गए। कार्यक्रम में पीएम ने चुनावों के बारे में बोलते हुए कहा, भारत में अब तक 17 आम चुनाव और 300 से अधिक राज्य विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2019 के आम चुनाव में जनता ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। 2019 का आम चुनाव मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अभ्यास थी। इसमें 60 करोड़ से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया। मोदी ने कहा कि 2024 में आम चुनाव के दौरान करीब 100 करोड़ यानी 1 अरब मतदाता वोट डालेंगे। मैं सभी प्रतिनिधियों को अगले आम चुनाव देखने के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम ने कहा, ईवीएम के इस्तेमाल से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है, क्योंकि अब वोटों की गिनती के कुछ घंटों के भीतर नतीजे घोषित हो जाते हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की जी20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत संसद द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम में जी20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्षों ने भाग लिया।

पिछले महीने नई दिल्ली जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के जी20 का सदस्य बनने के बाद पैन-अफ्रीकी संसद ने भी पहली बार पी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस पी20 शिखर सम्मेलन के दौरान विषयगत सत्र चार विषयों सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, एसडीजी में तेजी लाने और टिकाऊ ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित थे।

मोदी ने कहा कि हमारे पास बहस, विचार-विमर्श की हजारों वर्षों की विरासत है, हमारे 5,000 वर्ष से भी पुराने कुछ ग्रंथों में ऐसी प्रणालियों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग-अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। आप सभी प्रतिनिधि अलग-अलग संसदीय कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों में, उसके लोगों की आकांक्षाओं में निहित होती है! आज ये शिखर सम्मेलन भारत के लोगों की शक्ति का जश्न मनाने का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई हैं।

इजरायल-हमास युद्ध के बीच मोदी ने कहा कि यह सबके कल्याण और विकास का वक्त है। आतंकवाद दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह शांति और भाईचारे का समय है। उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। हमें विश्व को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से देखना होगा।

मध्यप्रदेश को लेकर कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक

कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन होगी जारी

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक की। इस मौके पर बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 140 उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दी गई है और यह सूची रविवार को जारी होने की संभावना है। सीईसी की बैठक के बाद विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बाकी नामों पर चर्चा के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी।

उम्मीदवारों की सूची की घोषणा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि काफी सीटों पर चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई...जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, यह दर्शाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा की है, फिर से हमारी बैठक होगी, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी सूची की घोषणा करेंगे। हम उस रफ्तार से चल रहे है कि 15 अक्टूबर को हम अपनी सूची की घोषणा कर सकें।

मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के माध्यम से, राज्य 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव करेगा। राज्य में एक चरण में चुनाव कराया जाएगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 41.5 फीसदी वोट शेयर के साथ 114 सीटें जीतीं जबकि बीजेपी को 41.6 फीसदी वोट शेयर के साथ 109 सीटें मिलीं। पिछले राज्य विधानसभा

चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आई थी, और अनुभवी नेता कमल नाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2020 में राज्य में एक राजनीतिक उथल-पुथल मच गई, जब तत्कालीन कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया, 22 वफादार विधायकों के साथ भगवा खेमे में चले गए। अल्पमत में आने के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा ने सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने।

छत्तीसगढ़ के 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी

कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए लगभग 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पुरानी सीट पाटन से चुनाव लड़ेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किसी भी मंत्री का टिकट नहीं काटेगी और सभी मंत्री एक बार फिर चुनावी रणभूमि में नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की शेष 42 सीटों पर एक से अधिक उम्मीदवार होने के कारण उम्मीदवारों का निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि 90 सीटों पर चर्चा हुई है, पूरी जानकारी रखी गई है..एक-दो दिन में फाइल स्थिति सामने आ जाएगी।

खेल
प्रमुख समाचार

विश्वकप में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज

अहमदाबाद। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच विश्व कप का मुकाबला खेला जाएगा। इस महामुकाबले पर सबकी नजर है। क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं तब न सिर्फ दोनों देशों की जनता बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर होती हैं। हालांकि विश्वकप में भारत को हराने का पाकिस्तान का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है। भारत से विश्वकप में जब भी पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है तब उसकी हार हुई है।

आईसीसी वनडे विश्वकप में भारत और पाकिस्तान पहली बार साल 1992 में भिड़े थे। सिडनी में हुए इस मुकाबले को भारत ने 43 रन से जीता था। साल 1996 में दोनों टीमों की भिड़ंत बेंगलुरु में हुई थी। यहां भी भारत ने 39 रन से बाजी मारी। 1999 के विश्वकप में मैनचेस्टर में हुए मैच में भारत ने एक बार फिर पाक टीम को 47 रन से पटकनी दी। साल 2003 के विश्वकप में भारत और पाकिस्तान सेंचुरियन में भिड़े थे। भारत ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर द्वारा खेली गई 98 रन की पारी को अब भी याद किया जाता है।

इसके बाद भारत पाकिस्तान की भिड़ंत साल 2011 के विश्वकप में हुई। मोहाली में खेले गए इस मैच में भारत एक बार फिर 29 रन से विजेता रहा। भारत ने इस साल विश्वकप भी जीता। 2015 में एडिलेड में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 76 रन से हराया। फिर साल 2019 में मैनचेस्टर में भारत डकवर्थ लुईस नियम से 89 रन से विजेता बना। अब अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को जब दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी तो भारत की नजर फिर से इतिहास दोहराने पर होंगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स - निफ्टी में दूसरे दिन भी गिरावट

नईदिल्ली। टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी, टीसीएस और बजाज ट्विन्स में मजबूत खरीदारी के बल पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को इंट्रा-डे ट्रेड के दूसरे सत्र में भारतीय इक्विटी बाजार ने स्मार्ट रिकवरी की। मगर फिर भी शेयर बाजार लाल निशान पर ही बंद हुए। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। आज ग्लोबल मार्केट में भी कमजोर रुझान देखे गए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 126 अंक टूटा। वहीं, निफ्टी में भी 43 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि व्यापक बाजारों ने बढ़त जारी रखी। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.1 फीसदी बढ़ा, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.2 फीसदी बढ़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 125.65 अंक यानी 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 66,282.74 अंक पर बंद हुआ।

भारत का निर्यात सितंबर में 2.6 प्रतिशत हुआ कम

नईदिल्ली। देश का निर्यात इस साल सितंबर में 2.6 प्रतिशत घटकर 34.47 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने में निर्यात 35.39 अरब डॉलर था। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में आयात भी 15 प्रतिशत घटकर 53.84 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने में यह 63.37 अरब डॉलर था। इससे व्यापार घाटा (trade deficit) सितंबर 2023 में 19.37 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-सितंबर के दौरान निर्यात 8.77 प्रतिशत घटकर 211.4 अरब डॉलर रहा। वहीं इन छह महीनों में आयात 12.23 प्रतिशत गिरकर 326.98 अरब डॉलर रहा। इस बीच, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, 'भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है और हम मतभेदों को दूर कर रहे हैं।'

ग्लोबल ब्रोकरेज की भारतीय बैंकों को लेकर बदली राय

नईदिल्ली। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने शुक्रवार, 13 अक्टूबर को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की रेटिंग को खरीदें से घटाकर बेचें कर दिया। यह ऋणदाता के लिए पहली बेचें रेटिंग है। इसके साथ ही लक्ष्य मूल्य में 740 रुपये से घटाकर 530 रुपये कर दिया गया, जो बैंक के स्टॉक प्रदर्शन पर उनके मंदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी ने पूरे सेक्टर पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और ईपीएस में 2 से 5 फीसदी की कटौता का भी ऐलान किया है। यूबीएस ने रेटिंग में बदलाव के पीछे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए बैंक के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में बढ़ती चिंता भी व्यक्त की। यूबीएस ने एक रिपोर्ट में कहा कि एसबीआई के सर्वोत्तम वित्तीय मेट्रिक्स पहले से ही रियरव्यू मिरर में हो सकते हैं। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2014 में रिटर्न अनुपात चरम पर होगा और वित्त वर्ष 2015 में गिरावट की उम्मीद है।

पोर्ट के बाद रिन्यूबल एनर्जी में भी अदाणी नंबर वन

नईदिल्ली। भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी की कंपनी इन दिनों ग्रीन एनर्जी पर खासा फोकस कर रही है। इस बीच, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कई जांच के दौर से गुजर रहा अदाणी ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूबल एनर्जी मैन्युफैक्तरिंग हब बनाने जा रहा है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट ने अदाणी सोलर के अधिकारियों के हवाले से बताया कि दुनिया का सबसे प्लांट गुजरात के मूंदड़ा में होगा। मनीकंट्रोल की इस रिपोर्ट में बताया गया कि अदाणी ग्रुप का यह प्लांट दुनिया का इकलौता ऐसा प्लांट होगा जहां रिन्यूबल एनर्जी के लिए लगने वाली सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसमें पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट्स, वेफर्स, सेल, सोलर मॉड्यूल के साथ-साथ विंड टर्बाइन भी शामिल है। कंपनी का प्लान सोलर ही नहीं, बल्कि विंड सेक्टर में भी उतनी ही तेजी से ग्रोथ करना है।

भारत की विकास दर के बारे में आईएमएफ का अनुमान राहत भरी है

प्रह्लाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। साथ ही, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा भी नहीं था कि आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिससे अब इजराइल एवं हमास के बीच युद्ध छिड़ गया है और अब तो एक तरह से लेबनान भी इस युद्ध में कूद गया है। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में अप्रैल-जून 2023 तिमाही में उम्मीद से अधिक खपत का हवाला देते हुए वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ की ओर से किया गया यह बदलाव भारत के आंकड़ों में किए गए कई बदलावों में सबसे नया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमानों के अनुसार वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। आईएमएफ के अनुसार आने वाले समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

आईएमएफ के पूर्व विश्व बैंक द्वारा भी एक ताजा प्रतिवेदन में यह अनुमान जताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3 प्रतिशत की दर से विकास करेगी। विकास की वजह देश में लगातार बढ़ रहा निवेश और घरेलू मांग का बढ़ना बताया गया है। विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट (आईडीयू) प्रतिवेदन में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन कायम है। इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार बनी रहेगी।

इसी प्रकार, आर्थिक विकास एवं

सहयोग संगठन (ओईसीडी) द्वारा जारी किए गए एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.3 प्रतिशत एवं वर्ष 2024 में 6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक वृद्धि दर रहने वाली है। जबकि इसी अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमश 3 प्रतिशत एवं 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। जी-20 समूह में शामिल विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2023 में 1.5 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

एक अन्य वैश्विक निवेश बैंक मार्गन स्टेनली द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि दर के बाद पूरे वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ाया गया है। मार्गन स्टेनली ने अब पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले मार्गन स्टेनली ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर को 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। निवेश बैंक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के चलते भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में संशोधन किया गया है। अप्रैल-जून 2023 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है, जो मार्गन स्टेनली के पूर्व अनुमान 7.4 प्रतिशत से अधिक है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते अब विश्व के कई देशों का चीन पर विश्वास लगातार कम हो रहा है, जिसके कारण विकसित देशों की कई कम्पनियां चीन से अपनी विनिर्माण इकाईयों को अन्य देशों में स्थानांतरित कर रही हैं। इससे चीन में कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस बीच भारत ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में अपनी विनिर्माण इकाईयां स्थापित करने हेतु आकर्षित करने उद्देश्य से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयों को अब भारत में स्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्मार्ट फोन उत्पादन, फार्मा, टेक्सटाइल, सुरक्षा उपकरणों के निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना की जा रही है।

अजीब तरह से गुजर रही है कुछ ऐसी जिंदगी.....

प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के नाम एक रिकार्ड बन गया है। चुनी हुई सरकार (मुख्यमंत्री गुजरात) से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक का 21 साल का सफर पूरा करके वे 22 वें साल में 7 अक्टूबर को प्रवेश कर गये हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद सम्हाला था वहीं 22 मई 14 तक वे इस पद पर अनवरत रहे हालांकि उनके मुख्यमंत्री रहने

का रिकार्ड उन्हीं की पार्टी के डॉ. रमन सिंह ने 15 साल लगातार सीएम बनकर छत्तीसगढ़ में तोड़ दिया है। अब तो लम्बे समय तक सीएम बने रहने का रिकार्ड (लगातार नहीं) मप्र के सीएम शिवराज सिंह के नाम हो गया है। बहरहाल 26 मई 2014 को नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वे निरंतर हैं। वैसे उनका प्रधानमंत्री रहने का रिकार्ड बनाने में अभी काफी समय लगेगा। उन्हें पीएम बने साढ़े 9 साल से अधिक समय हो चुका है। जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लालनेहरू 6130 दिन, इंदिरा गांधी 5829 दिन, डॉ. मनमोहन सिंह 3656 दिन,अटल बिहारी वाजपेयी 2272 दिन, राजीव गांधी1857 दिन,पी.वी. नरसिम्हा राव 2229 दिन रहे। जहां तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने की बात है तो कई नेता भी रह चुके हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी भाई देसाई 1655 दिन मुख्यमंत्री तथा 856 दिन प्रधानमंत्री रहे,पी.पी. नरसिम्हा राव 468 दिन मुख्यमंत्री तथा 1761 दिन प्रधानमंत्री रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह 739 दिन मुख्यमंत्री, 346 दिन प्रधानमंत्री, इस तरह सक्रिय रूप से सत्ता में 1082 दिन पद पर रहे, एच.डी. देवेगौड़ा 538 दिन मुख्यमंत्री, 324 दिन प्रधानमंत्री कुल 862 दिन, चौधरी चरण सिंह 553 दिन मुख्यमंत्री तथा178 दिन प्रधानमंत्री कुल 723 दिन रहे तो लालबहादुर शास्त्री 581,आई के गुजराल 332,चंद्रशेखर 223 तथा गुलजारी लाल नंदा 26 दिन बतौर प्रधानमंत्री रहे।वैसे नरेंद्र मोदी अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में अचानक नोटबंदी,नया जीएसटी लागू करने, कोरोना महामारी काल में करोड़ों के बेरोजगार होने, देश के आर्थिक हालात बिगड़ने , विपक्ष से अच्छे संबंध नहीं, द्वसंघीय व्यवस्था में चुनी हुई राज्य सरकारों से बिगड़ते रिश्ते,पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं होने,अपनी ही पार्टी में एकला चलो (अमित शाह को छोड़कर) की नीति के कारण भी जाने जाते रहे हैं।

डॉ रमन ने टिकट के लिये दबाव नहीं बनाया....?

छत्तीसगढ़ मेंअविभाजित मप्र के सीएम रहे

श्यामचरण शुक्ला के बारे में कहा जाता था कि वे अपने समर्थकों को टिकट दिलाने भरपूर प्रयास करते थे,बाद में उनके बेटे अमितेश शुक्ला के लिये अपनी राजिम की सीट छोड़ दी... कारण जो भी रहा हो पर यदि छ्ग राज्य बनते समय श्यामा भैया विधायक होते तो अजीत जोगी की जगह सीएम बन सकते थे? अब दूसरे सीएम रहे मोतीलाल वोरा की बात कर लें... वे हर विधानसभा चुनाव में अपने कुछ समर्थकों के लिये टिकट मांगते थे पर आख़री दौर में अपने बेटे अरुण वोरा के लिये ही अड़ जाते थे... समर्थकों के लिये दबाव बनाने से पीछे हो जाते थे। छ्ग के पहले सीएम, पूर्व नौकरशाह अजीत जोगी जरूर अपने समर्थकों को टिकट दिलाने अड़ जाते थे।मप्र और छ्ग में भी... पर बाद में पुत्र मोह के चलते वे इस हद तक चले गये कि उन्हें कॉंग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाना पड़ा... उनकी पत्नी डॉ रेणु जोगी और पुत्र अमित जोगी विधायक बन चुके हैं पिछली बार तो उन्होंने अपनी बहु ऋचा जोगी को भी चुनाव समर में उतार दिया था। अब 15 साल भाजपा के लगातार सीएम बनने का रिकार्ड बनाने वाले डॉ रमन सिंह की बात कर लें.. पहले बतौर सीएम उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया वहीं अपने बेटे अभिषेक सिंह को भी सांसद बनवा दिया था यह बात और है अभिषेक कि दूसरी पारी शुरू नहीं हो सकी? इस बार डॉ रमन सिंह तथा उनके भांजे विक्रम सिँह विस चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सीएम कार्यकाल में कलेक्टरी छोड़कर भाजपा में शामिल होनेवाले ओ पी चौधरी को टिकट मिली है तो रिटायर आईएएस नीलकंठ टेकाम को भी टिकट दिलाने में डॉ रमन की भूमिका रही पर प्रमुख सचिव पद से रिटायर गणेश शंकर मिश्रा को टिकट दिलाने डॉ साहब ने लगता है दबाव नहीं बनाया... नहीं तो छत्तीसगढ़िया फ़िल्म कलाकार अनुज शर्मा को टिकट नहीं मिलती...? भाजपा के कार्यकाल में अनुज को पद्मश्री मिला, पत्नी को रविशंकर विवि में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक की नौकरी मिली.... खैर डॉ रमन के कवर्धा विस चुनाव में (तब एसडी?म)राजनांद गांव में कलेक्टर आदि के पद पर रहे आईएएस जीएस मिश्रा,डॉ रमन सिँह के काफ़ी करीबी अफसर माने जाते हैँ, उन्ही के कहने पर रिटायर होने के बाद भाजपा में शामिल हो गये पर उन्हें भाजपा ने टिकट देने के योग्य भी नहीं समझा... डॉ रमन ने भी तो इनके लिये दबाव नहीं बनाया...?

भाजपा के सभी बड़े नेता प्रत्याशी,तो प्रचार कौन करेगा....

भाजपा के घोषित 85 प्रत्याशियों में पूर्व सीएम, पूर्व

मंत्री, भाजपा अध्यक्ष, भाजपा के 3 महामंत्री 4सांसद, एक केंद्रीय राज्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सभी प्रत्याशी बनाये गये है तो क्या चुनावी केम्पन कौन सम्हालेगा, क्या बाहरी नेता....? कुल मिलाकर आदिवासी समाज से 30अनुसूचित जाति से 10पिछड़ा वर्ग से 31प्रत्याशी है।सूची में अब तक 14महिलाओं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। 43 ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है जो पहली बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। 50 वर्ष से कम आयु के 34 युवा प्रत्याशी हैं।भाजपा की सूची में एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर युवा और नए प्रत्याशी हैं,वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है जिसमें कुछ तो पिछला चुनाव हजारों मतों से हारे हैं इसमें रमन सरकार के 17 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं।भाजपा ने सरगुजा से सांसद व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से चुनावी मैदान में उतारा गया है।वहीं सांसद गोमती साय को पत्थल गांव से मौका दिया गया है। इसके अलावा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव लोरमी विधानसभा से मैदान पर होंगे। वहीं भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी, विजय शर्मा,केदार कश्यप भी शामिल हैं।जबकि पहली सूची में विजय बघेल को पाटन से मैदान में उतारा जा चुका है। मतलब चार सांसद विधायक बनने की तैयारी में हैं।अब पते की बात ये है कि चुनाव जीत गए तब तो ठीक है कि विधायक बन जायेंगे। हार गए तो निश्चित मानकर सांसद के लिए टिकट मिलना भी नहीं हैं और मांग भी नहीं सकते? मतलब बोरिया बिस्तर सिमटना तय है।

और अब बस...

- मोदी सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है।
- कवर्धा और बेमेतरा में विस चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना है ?
- पितृपक्ष के बाद नवरात्रि में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा होना तय है ?

गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी की झूठी अफवाह : डॉ. रमन सिंह

- **कांग्रेस का पीएम मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश**

रायपुर। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार पर गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का आरोप लगाते हुए सोशल मिडिया पर पोस्ट किया था जो सिर्फ एक अफ़वाह निकला और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (छ्क्क्ष्ठ) ने स्पष्ट किया है कि 'गंगाजल' को जीएसटी से छूट दी गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस को करार जवाब दिया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दाऊ

भूपेश बघेल आपको और कांग्रेस को सनातन से इतनी नफ़रत क्यों है? पहले गंगाजल की झूठी कसम खाकर सरकार बनाई और अब गंगाजल पर जीएसटी का भ्रम फैलाकर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो अपनी जगह है पर इतना तो लिहाज़ करो कि अंतिम समय में सबको माँ गंगा की शरण में जाना है। माँ गंगा को अपमानित करना बंद करिए वरना आपके काले कारनामों के पाप गंगाजल से भी नही धुलेंगे।

कांग्रेस का तुष्टिकरण मूर्ति ध्वंस का जिम्मेदार: बृजमोहन

- **कांग्रेस की कठपुतली बनने से बाज आये प्रशासन**
- **हार से भयभीत कांग्रेस बिगाड़ना चाहती है माहौल**

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता, विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संस्कृति धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भिलाई में विगत रात्रि देवाधिदेव भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां खंडित किए जाने की घटना के संदर्भ में रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस शासन काल में 5 साल तक धार्मिक तुष्टिकरण के लिए सनातन संस्कृति का अपमान करने वालों को संरक्षित किया गया है, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ में जगह-जगह देखने मिला है

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वह तुष्टिकरण की ही राजनीति है जिसकी वजह से आदिवासी अंचलों में पुरातन संस्कृति का अवमूल्यन करने के लिए धर्मांतरण को सुनियोजित रूप दिया गया। वह तुष्टिकरण की ही राजनीति है, जिसके तहत कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान किया गया और सनातन धर्म की ध्वज रक्षा करने वालों को जेल में ठूंसा गया यह तुष्टिकरण की ही राजनीति है कि बिरनपुर में निर्दोष हिन्दू युवक की जेहादियों ने हत्या की और कांग्रेस सरकार ने नामजद सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय निर्दोष हिन्दू युवाओं पर मुकदमा लादकर जेल भेज दिया। न्याय के मंदिर में ही उन बेकसूरों को न्याय मिला।यह तुष्टीकरण की ही राजनीति है कि भिलाई के संतोषी पारा में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को खंडित किया गया है।बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कभी भी किसी भी धर्म आस्था के केंद्र में इस तरह की कुंठित मानसिकता के हमले पहले नहीं होते थे।

राजेश मूणत का धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जारी, आमजनता के बीच जाकर कर रहे हैं संवाद

रायपुर। पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत का धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जारी है। शुक्रवार को उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 7 बैठके भी ली। मूणत ने बैठकों के माध्यम से आम जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। विशेष बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने महिला मतदाताओं के साथ मुलाकात करके कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर उनके विचार भी सुने। शुक्रवार को हुई बैठकों की शुरुआत सुबह 11 बजे राजेश मूणत के निवास कार्यालय से हुई,जहाँ उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस

दौरान श्री मूणत ने महिलाओ को बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढे अपराध और शराबबंदी का झूठा वादा महिलाओं के लिए प्रमुख मुद्दा होंगे। उन्होने बैठक में निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा के पक्ष में प्रचार के लिए खुद को व्यस्त कर लेना चाहिए। राजेश मूणत ने इसके बाद क्रमशः शहीद चूड़ामड़ी वार्ड, स्वामी आत्मानंद वार्ड, शहीद मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड, वीर सावरकर वार्ड और तात्यापारा वार्ड में जनसभा की। श्री राजेश मूणत ने बताया कि वह अब तक रायपुर पश्चिम विधानसभा के कुल 20 वार्डो में से 16 वार्डो में कार्यकर्ताओं और आमजनो के बीच जाकर बैठक कर चुके है। उन्होंने बताया कि भाजपा की इन बैठकों में महिलाये बड़ी संख्या में पहुंच रही है। सभी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद से उनके क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। जुआ, नशाखोरी, अवैध शराब की बिक्री, चाकूबाजी और छेडछाड की घटनाये बढ़ी हैं। राजेश मूणत ने बताया कि जहां जा रहे हैं, लोग कह रहे है कि कांग्रेस ने रायपुर की सड़कों को बर्बाद करके उसे खोदपुर बना दिया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

इस चुनाव में भाजपा जनता से माफीनामा जारी करें: बैज

रायपुर। इस चुनाव में भाजपा जनता से माफीनामा जारी करें। भाजपा को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिये जनता ने उन्हें तीन बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था उस घोषणा पत्र के वायदो को पूरा करने के लिये तीन बार सरकार चलाने का अवसर दिया था लेकिन भाजपा वायदा करके वो मुकर गयी। 2003 के घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार

से एक को सरकारी नौकरी देने का, युवाओं को 500 रू. बेरोजगारी भत्ता देने का, 2008 में वायदा किया किसानों को धान का 300 रू. बोनस देने का, 2013 में वायदा किया था धान की कीमत 2100 रू. देंगे और 300 रू. बोनस कुल 2400 रू. प्रति क्विंटल धान खरीदी करने का कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। एक बार फिर से जनता को ठगने के लिये घोषणा पत्र बनाने जनता के बीच जाने की बात कर रहे है। अब जनता उनके घोषणा पत्र में क्यों भरोसा करेगी? हमने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया हमारे 36 में से 34 वायदें पूरा हुये। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक मुख्यमंत्री अपने वायदा को पूरा कर रहे है। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते 15 साल वादाखिलाफी करने वाले भाजपाई किस नैतिकता से नये वादो की बात कर रहे है? मन की बात करना और मनमानी थोपना ये भाजपा का राजनैतिक चरित्र है।

टिकट कटने से नाराज चोपड़ा हो सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी

महासमुंद। भाजपा के कद्दावर नेता डा. विमल चोपड़ा को पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर उनकी नाराजगी उभरकर सामने आ गई है। पार्टी के प्रति वफादारी और अपने साफगोई व्यावहार से जनता के बीच में छवि बनाने वाले डा. विमल चोपड़ा ने टिकट काटे जाने पर पार्टी के नेताओं को जहां आड़े हाथों लिया वहीं उन्होंनें अपने समर्थकों के समक्ष एक-दो दिनों में स्थिति स्पष्ट करने का ऐलान कर दिया। डा.

विमल चोपड़ा महासमुंद की राजनीति में पिछले अनेक वर्षों से जबर्दस्त दखल बनाए हुए है। इससे पहले भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। महासमुंद से इस बार भाजपा ने डा. विमल चोपड़ा के स्थान पर योगेश्वर राजू सिन्हा पर दांव लगाया है और उसे प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद डा. विमल चोपड़ा पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे। आखिरकार उनकी नाराजगी अपने समर्थकों के साथ छलक आई। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका कोई पिताम्ह नहीं है और न ही वे किसी की लल्लो-चप्पो करते है, नतीजा यह है कि उनकी टिकट कांट दी गई। टिकट कांटे जाने का कारण जातिगत समीकरण को बताया गया है। डा. चोपड़ा ने कहा कि विडंबना यह है कि पार्टी एक ओर जाति समीकरण की दुहाई दे रही है वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव से डा. रमन सिंह और खैरागढ़ से वीरेंद्र सिंह को टिकट दी है, याने मामा और भांजा दोनों चुनाव लड़ेंगे। अब जाति और परिवार कसौटी पर है।डा. चोपड़ा के समर्थकों ने उनकी टिकट कांटे जाने पर पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाया था लेकिन उसका नतीजा सिफर रहा।

आम नागरिकों के लिए सी-विजिल एप्प होगा अमोघ अस्त्र

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन 2023 में उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए आम नागरिक भी सी-विजिल फोन एप्प के माध्यम से डराने, धमकाने या प्रलोभन देने की शिकायतें सीधे भारत निर्वाचन आयोग को कर सकेंगे। इस बार साफ-सुथरे, निर्विवाद और पारदर्शी चुनाव के लिए सी-विजिल एप्प आम नागरिकों के मोबाईल फोन पर अमोघ अस्त्र के रूप में इंस्टाल रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या किसी राजनैतिक दल और प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने या पैसा, शराब, सामग्री बांटकर अपने पक्ष में मतदान के लिए मजबूर करने की शिकायतें करने के लिए सी-विजिल मोबाइल एप्प का निर्माण कराया गया है। एप्प को बिना किसी परेशानी के संचालित होने के लिए सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह एप्प मतदाताओं के लिए एक्टिवेट हो गया है। लोग इसे गुगल एप्प स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकेंगे। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालकर स्वयं पंजीकृत होना पड़ेगा। विधानसभा निर्वाचन को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आम नागरिकों को 24 घंटे निगरानी की सुविधा देने वाले इस एप्प से लोग घटनाओं के फोटो या वीडियो लेकर सीधे अपलोड कर सकेंगे। इस एप्प के माध्यम से लिए गये फोटो या वीडियो मोबाइल फोन में सेव नहीं होंगे बल्कि सीधे निर्वाचन आयोग कार्यालय या जिला नियंत्रण कक्ष को प्राप्त होंगे।

बघेल के कारनामे देखकर वाकई दुनिया चकित है : शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल तक घपले घोटाले कमीशनबाजी भ्रष्टाचार माफियाराज चलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। वह बघेल सरकार के पापों पर पर्दा डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह सिरे नहीं चढ़ने वाली। उन्हें भ्रम हो गया है कि वह छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल के गुणगान सुना जाएंगे और यहां की जनता उनकी बातें सुन लेगी।भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो भी नेता आता है, वह भूपेश बघेल की शान में तरह-तरह के अफसाने सुना कर चला जाता है। चाहे राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुनखड़गे हों, प्रियंका गांधी हों या खेड़ा जैसे कांग्रेस के कोई भी नेता हों, यह सभी भूपेश बघेल का यश गान करने के लिए विवश हैं बल्कि अभिशप्त हैं। क्योंकि भूपेश बघेल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसी के पैसों से कांग्रेस देश भर में चुनाव लड़ रही है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर कोई भूपेश बघेल सरकार की करगुजारियों से परिचित है। इसलिए खेड़ा को सोच समझकर दावे करना चाहिए। हकीकत यह है कि भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। भाजपा की मोदी सरकार ने पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की जनता का ख्याल रखा। भूपेश बघेल सरकार तो कोरोना काल से दिया जा रहा गरीब का अतिरिक्त अनाज तक खा गई। ऐसी सरकार के बारे में खेड़ा कह रहे हैं।

विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत

रायपुर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत हो गई. पहले दिन 20 विधानसभा सीटों के लिए किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया. प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 समेत राजनांदगांव, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी , खैरागढ़- छुईखदान- गंडई और कबीरधाम जिलों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है.प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं. 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. वहीं प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे. पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दोनों ही चरणों के मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी.पहले चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर, नारायणपुर , कोंडागांव ,केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापुर, अंतागढ़, मोहला- मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा.

सवाल, जवाब और सियासत

कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर से किया सवाल, कहा-

अपने मंत्रिमंडल के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराती मोदी सरकार

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और पीसीसी संचार अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेसवार्ता कर सवाल पूछा है. उन्होंने कहा कि क्या भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उनके मंत्री मंडल में लगे आरोपों की जांच मोदी सरकार से करवाएंगे?

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद आये थे, वे एक बार फिर झूठ परोस गये. जिन रविशंकर की आजकल भाजपा में कोई नहीं सुन रहा है. वे छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ सुनाने आये थे.

रविशंकर मुद्दाविहीन भाजपा के प्रलापों को आगे बढ़ा गये. कांग्रेस ने रविशंकर प्रसाद और भाजपा से 9 सवाल कर जवाब मांगा है.

रमन सिंह के और उनके मंत्रियों के 1 लाख करोड़ के घोटाले पर क्यों चुप है रविशंकर प्रसाद? बतायें 36000 करोड़ के नान घोटाले और 6200 करोड़ के चिटफंड घोटाले, पनामा पेपर घोटाले पर मोदी सरकार जांच क्यों नहीं करवाती?अडानी के घोटालों पर क्यों मौन है? देश आज भी जानना चाहती है अडानी की कंपनियों में 20 हजार करोड़ किसके लगे है?भाजपाई खुद को सनातनी बताते हैं तो बतायें 15 सालों में माता कौशल्या के मंदिर और राम वन गमन पथ को उपेक्षित क्यों रखा? राम वन गमन पथ को क्यों नहीं बनाया?

महादेव एप्प पर केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं लगाती? महादेव एप पर कार्रवाई करने गई छत्तीसगढ़ सरकार को योगी सरकार ने मुकदमा क्यों दर्ज किया? आरोपियों को क्यों बचाया? महादेव एप पर कार्रवाई तो अकेले छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है.भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता जो एक राज्य में महत्वपूर्ण पद पर है, जो छत्तीसगढ़ से आते है. उनका महादेव एप्प के सरगना और उसके सहयोगी से क्या संबंध है?7 लाख प्रधानमंत्री आवास को मोदी सरकार ने क्यों रोका था? जिसके कारण भूपेश सरकार को ग्रामीण आवास योजना शुरू करना पड़ा और आवासहीनों के खाते में पहला किश्त भी डाल दिया.भाजपा बतायें वह जातीय जनगणना के पक्ष में है या खिलाफ में? भाजपा देश की जनगणना क्यों नहीं करवा रही है?केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से चावल लेने का कोटा क्यों घटाया? 86 लाख की एमओयू करके उसे 61 लाख क्यों किया? भाजपा ने राजभवन में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को रोकने का षड़यंत्र किया जिसमें एसटी को 32 प्रतिशत, एससी को 13 प्रतिशत, आर्थिक पिछड़े को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया.

पहले चरण में 20 सीटों पर 39 लाख 23 हजार मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे: साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से पहले चरण के 20 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण के 20 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है वहीं कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है । ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, 2 दिनों से चल रहे कैंडी क्रश विवाद के साथ तंज कसा है। अरुण साव ने सोशल मीडिया एक्स में तंज कसते

हुए लिखा है– आज से पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो रही है..! उधर पोगो और कैंडी क्रशवालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए चुनावी मैदान के लिए..! तैयार हो जाओ भाई, डरो मत! भाजपा अध्यक्ष साव ने कांग्रेस के स्लोगन हैं तैयार हम पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उठे सवाल का भी करारा जवाब देते हुए लिखा है तैयार हो जाओ भाई डरो मत। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की आठ सीट शामिल हैं। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है, उनमें भाजपा ने सभी सीटों प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को घोषित हो सकती है। पहले चरण में 20 सीटों पर 39 लाख 23 हजार मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.